हिमाचल की प्रगति एवं संस्कृति का दर्पण

गिरिराज

साप्ताहिक

Mkd iathdj.k la[;k ,p-ih-@42@,l-,e-,y- 2009 lkIrkfgd vkj-,u-vkbZ- 32195@78

o"kZ 31 vad 48 f'keyk] 2&8 flrEcj] 2009 gj c/kokj dks çdkf'kr eY; % ,d izfr 3-00 #i;s okf"kZd 140 #i;s vkthou 1500 #i;s website : himachalpr.gov.in/giriraj.asp

घर बैठे गिरिराज पाइये

गिरिराज का आजीवन ग्राहक बनने के लिए सदस्यता शुल्क 1500 **रुपये** बैंक ड्राफ्ट या मनिआर्डर के माध्यम से **निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, शिमला**–2 व वार्षिक सदस्य बनने के लिए सदस्यता शुल्क 140 **रुपये, सम्पादक, गिरिराज साप्ताहिक, शिमला**–171005 के नाम से भेजे।

ir s e s fiu dksM ,o

njHkk"k ;k ekckby u- fy[kuk u Hkwy s

इस अंक में

कृषि/बागबानी/विकास...	5
आस्था/संस्कृति/विविध...	6
विविध...	7
साहित्य...	8
महिला/बाल जगत/स्वास्थ्य ...	9
पहाड़ी पृष्ठ	10

पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की अधिसूचना जारी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश मंत्रिमण्डल ने गत 24 अगस्त को एक सितम्बर से प्रदेश के सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को वेतनमान देने का निर्णय लिया। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी, 2006 से लागू होंगी। कर्मियों को जनवरी, 2009 से देय महंगाई भत्ते की किश्त भी जारी कर दी गई है। कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन सितम्बर माह से मिलेगा।

जल संरक्षण उपाय अपनाने वालों को पुरस्कृत करेगी सरकार

मुख्य मंत्री ने की नव गठित जलप्रबन्धन बोर्ड की अध्यक्षता

प्रदेश सरकार जल संरक्षण एवं जल के समुचित उपयोग को सुनिश्चित बनाने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन के तौर पर पुरस्कृत करने पर विचार करेगी। मुख्य मंत्री प्रो0 प्रेम कुमार धूमल ने यह जानकारी गत दिनों शिमला में नवगठित जल प्रबंधन बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

मुख्य मंत्री ने कहा कि मानव जाति, पेड़-पौधों एवं जीव जन्तुओं को जीवित रखने के लिए जल की महत्त्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसके समुचित उपयोग को सुनिश्चित बनाने की अति आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जल स्रोतों के सुनियोजित प्रबंधन को सुनिश्चित बनाने के दृष्टिगत जल प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया है तथा इसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को पानी की हर बूंद को सुरक्षित रखने के लिए सम्बद्ध करना है। उन्होंने कहा कि बोर्ड का मुख्य लक्ष्य पंचायती राज संस्थानों, स्थानीय शहरी निकायों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं को जल प्रबंधन के लिए शामिल कर सशक्त करना है। इसके अतिरिक्त जल संरक्षण एवं जल के सुनियोजित उपयोग के लिए पुरस्कार के तौर पर प्रोत्साहन योजना को आरंभ करना भी बोर्ड का लक्ष्य है।

प्रो0 धूमल ने कहा कि भूमण्डलीय उष्मीकरण, पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं ग्लेशियरों के पिघलने के कारण पारंपरिक जल स्रोत तेजी से सूख रहे हैं, जिससे प्रदेश में मौजुदा जलापूर्ति नेटवर्क में कमी आई है। उन्होंने शंका व्यक्त की कि इस तरह के पर्यावरण में आ रहे बदलाव के चलते जलस्रोतों के सूखने के कारण जल आवश्यकता एक गंभीर चुनौती न बन जाए। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगीकरण तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से उपलब्ध जल की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य में 7506 जलापूर्ति योजनाओं, 4 मध्यम सिंचाई योजनाओं, 960 सिंचाई योजनाओं, 542 उठाऊ सिंचाई योजनाओं, 550 ट्यूबवैल पर आधारित सिंचाई योजनाओं तथा लगभग 20 हजार हैण्डपंपों के व्यापक नेटवर्क को सृजित करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया है। इसके अतिरिक्त पारंपरिक सिंचाई नहरों के रखरखाव पर व्यापक व्यय किया गया है। उन्होंने कहा कि बड़ी, मध्यम एवं छोटी

(शेष पृष्ठ 11 पर)

सिंगापुर कम्पनी द्वारा पौधरोपण में एक हजार करोड़ निवेश का प्रस्ताव

सिंगापुर से सम्बन्धित बहुराष्ट्रीय कंपनी एम.जी. इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी अनेक देशों में वन प्रबंधन इकाइयां कार्यरत हैं, ने हिमाचल प्रदेश में वनीकरण क्षेत्र में विश्वस्तरीय पौधरोपण क्षेत्र एवं वन उत्पादन इकाइयां सृजित करने के लिए 1000 करोड़ रुपये के निवेश की इच्छा व्यक्त की है। कंपनी के महाप्रबन्धक श्री रणवीर सिंह राणा तथा वित्त एवं परियोजना प्रमुख श्री विकास अग्रवाल के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने गत दिनों शिमला में अपने निवेश प्रस्तावों को लेकर मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल से भेंट की।

(शेष पृष्ठ 11 पर)

मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल शिमला ग्रामीण उपमण्डल के नेहरा घरयोग ग्राम पंचायत में देवदार का पौधा लगाते हुए।

मुख्य मंत्री द्वारा वृक्षारोपण को जनअभियान बनाने का आह्वान

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण को जन अभियान बनाने का आहवान किया है ताकि प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य एवं निर्मल पर्यावरण को बनाए रखा जा सके। मुख्य मंत्री गत दिनों शिमला ग्रामीण उपमंडल के नेहरा घरयोग ग्राम पंचायत के नेहरा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व, उन्होंने राज्य भाजपा महिला मोर्चा द्वारा घरयोग में वृक्षारोपण के अवसर पर देवदार का पौधा लगाया। इसके उपरांत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्रीमती सरवीण चौधरी, सांसद श्री वीरेन्द्र कश्यप तथा राज्य भाजपा महिला मोर्चा के अन्य पदाधिकारियों ने भी पौधरोपण किया।

प्रदेश में वृक्षारोपण एवं वनीकरण में राज्य महिला मोर्चा की भागीदारी की सराहना करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि इससे अन्य संगठन भी पौधरोपण में सहयोग के लिए प्रेरित होंगे, जिससे वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि गैर सरकारी संगठन तथा अन्य स्वयंसेवी संगठन भी वृक्षारोपण में आगे आ रहे हैं।

प्रो. धूमल ने कहा कि प्रदेश के पुराने वनों को पुनर्बहाल करने की आवश्यकता है, ताकि पुराने वृक्षों के स्थान पर नये वृक्ष उगाए जा सकें। उन्होंने कहा कि वन प्रदेश की सबसे

पुराने वनों को पुनर्बहाल करने की आवश्यकता

बहुमूल्य संपदा है, जिसे हर कीमत पर संरक्षित करने की आवश्यकता है। उन्होंने वृक्षारोपण को जन अभियान बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक उष्मीकरण की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए वृक्षारोपण को जन अभियान बनाने में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए।

मुख्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने निजी भूमि पर उगे वृक्षों का उपयोग करने का अधिकार भू-स्वामियों को देने का मामला उठाया है जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश सरकार निजी भूमि पर उगे वृक्षों के मालिकाना हक भू-स्वामियों को हस्तांतरित करने में सफल रही है।

प्रो. धूमल ने शिमला नगर के प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए गैर सरकारी संगठन की भूमिका की सराहना की, जिसने शिमला नगर के वनों के वैभव को बनाए रखने में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के वन विभाग तथा 11 गैर सरकारी संगठनों एवं स्थानीय संगठनों द्वारा 'देवदार पुनर्जीविकरण' अभियान का आरंभ किया गया है, ताकि देवदार को पूर्ण संरक्षण मिल सके। उन्होंने आशा व्यक्त की कि समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी से शिमला पुन: देश का 'देवदार वन नगर' बन कर उभरेगा।

मुख्य मंत्री ने वनों के संरक्षण तथा पर्यावरण विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखा जा

(शेष पृष्ठ 11 पर)

युवा अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लगायें -राज्यपाल

श्रीमती प्रभा राव ने प्रदेश के युवाओं से राष्ट्र निर्माण में अपने आपको समर्पित करने का आह्वान किया है। राज्यपाल गत दिनों शिमला के राजभवन में हिमाचल प्रदेश नेहरू युवा केन्द्र संगठन के 'नेशनल सर्विस वॉलंटियर्स' को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी ऊर्जा को राष्ट्र के सुदृढ़ीकरण में लगाना चाहिए।

श्रीमती राव ने युवाओं से पंडित जवाहर लाल नेहरु द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का आग्रह किया, जिनके नाम से इस संगठन का नाम रखा गया है, ताकि राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय मूल्यों, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, जल संरक्षण एवं युवा सशक्तिकरण के लिए युवाओं को प्रेरित किया जा सके। नेहरु युवा केन्द्र संगठन का लक्ष्य युवाओं को नैतिक मूल्यों एवं दक्षता को विकसित करना है ताकि वे देश के जिम्मेदार नागरिक बन सकें।

स्वयंसेवियों के साथ विचार-विमर्श करते हुए श्रीमती राव ने कहा कि किसी को भी हमारे समाज में लड़कों एवं लड़कियों में भेद नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में सुदृढ़ एवं विकसित राष्ट्र के निर्माण में लड़कियों का भी बराबर का स्थान है। उन्होंने युवा सशक्तिकरण की महत्ता पर भी बल दिया।

नेहरु युवा केन्द्र के हिमाचल प्रदेश अंचल के निदेशक श्री अलवन मसीह ने राज्यपाल का स्वागत किया।

नेहरु युवा केन्द्र के उप निदेशक श्री अनिल कौशिक ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

राज्यपाल के सचिव श्री भरत खेड़ा तथा नेहरु युवा केन्द्र के अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

विधायकों के संशोधित वेतनमान विधेयक पारित

प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्रियों, मुख्य संसदीय सचिव, संसदीय सचिव एवं विधायकों को बढ़े हुए संशोधित वेतनमान देने बारे सदन में लाए गए विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने केंद्र सरकार से मांग की कि चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए यदि संभव हो, तो संसद में एक विधेयक लाना चाहिए। यह विधेयक उसी तरह होना चाहिए, जैसे कर्मचारियों के लिए अलग से वेतनमान गठित किए जाते हैं। इससे जहां कोई निर्वाचित प्रतिनिधियों पर अंगुली नहीं उठाएगा, वहीं उनको भी जनता के बीच जाकर स्पष्टीकरण नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सभी को 16 हजार रुपये की वृद्धि की गई है। उन्होंने

(शेष पृष्ठ 11 पर)

पेपर मूवमेंट ऑन लाईन

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने विधायक श्री राकेश पठानिया द्वारा सदन में उठाये गये एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि सचिवालय स्तर की सभी शाखाओं/कार्यालयों में पेपर मूवमेंट पहले से ही REFNIC सिस्टम के द्वारा ऑन लाईन है।

उन्होंने बताया कि सचिवालय स्तर पर सभी शाखाओं/ कार्यालयों में पेपर मूवमेंट का सभी स्तरों पर एकत्र सरकारी डाक का ब्यौरा REFNIC में विभिन्न स्तरों पर मिलता है। इसमें सम्बन्धित विभाग के सहायक के पास लम्बित डाक/पेपर का ब्यौरा भी उपलब्ध रहता है।

सरकारी विभाग की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए ई-समाधान प्रणाली शुरू की गई है जिसकी शुरूआत 27.12.2008 को की गई है। इस प्रणाली के अंतर्गत विभागों के द्वारा प्रदत्त सेवाओं के कार्य को निपटाने हेतु समयबद्ध सीमा निर्धारित करते हुए मापदण्ड निश्चित किये गये हैं तथा उन मापदण्डों की अवहेलना होने पर प्रत्येक नागरिक ऑन लाईन शिकायत कर सकता है और समय-समय पर विभागों द्वारा की गई कार्यवाही का भी अवलोकन कर सकता है। यह प्रणाली चरणबद्ध ढंग से सभी विभागों में लागू की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कर्मचारी के उत्तरदायित्वों की सूची बनाने तथा भौतिक व वित्तीय उपलब्धियों के साथ-साथ आकलन हेतु कार्य निष्पादन सूचक बनाये जा रहे हैं। ई-समाधान प्रणाली के अंतर्गत अभी तक कुल 3259 शिकायतें दर्ज हुई हैं तथा 2099 शिकायतों का निपटारा विभिन्न विभागों द्वारा किया गया है।

सौ नये डॉक्टर होंगे भर्ती

हिमाचल प्रदेश सरकार आगामी सितम्बर माह से सौ नये डॉक्टरों की भर्ती करेगी। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव बिंदल ने विधानसभा में दी। वह स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर विधायक ठाकुर कौल सिंह द्वारा लाये गये एक प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। बिंदल ने बताया कि सरकार नये भर्ती किये जाने वाले डॉक्टरों को राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में भेजेगी ताकि दूरदराज के क्षेत्रों में भी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलबध हो सकें। उन्होंने बताया कि हाल ही में किन्नौर, लाहौल-स्पीति और भरमौर में नये डॉक्टरों की नियुक्तियां की गई हैं। राज्य में नर्सों की कमी को पूरा करने के लिए नये नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं। इन संस्थानों के जरिये हर साल 1700 नई नर्सें राज्य में उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2007-08 के दौरान जहां डॉक्टर की भर्ती नहीं की गई वहीं वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के बाद अभी तक कुल 315 भर्तियां कर दी हैं। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश को मिल रहे पैसे का हवाला देते हुए इस बात को गलत बताया कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में प्रदेश को मिशन के तहत अधिक पैसा मिला। डॉ. बिंदल ने बताया कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य में कांगड़ा तथा शिमला जिला के गरीब परिवारों को स्मार्ट कार्ड जारी करने का फैसला लिया है।

दुग्ध उत्पादकों को मिल रहे अच्छे दाम

मण्डी जिला की बल्ह घाटी की ग्राम पंचायत कुम्मी तथा खांदला के गांव घट्टा, खांदला, घुम्मी, भिथूरा तथा छपरोहल गांव के वाशिंदों के लिए घट्टा दुग्ध उत्पादन सहकारी सभा का गठन उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों में सहकारी सभा के माध्यम से दुग्ध विक्रय करने पर उचित मूल्य समय पर प्राप्त होने तथा प्रदेश सरकार द्वारा गत एक वर्ष में दूध के मूल्य में चार रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। ग्रामीण विकास अभिकरण के सौजन्य से स्थापित 500 लीटर वल्क मिल्क कलेक्टर तथा प्रदेश सरकार द्वारा मिल्क फैड के माध्यम से दुग्ध एकत्रीकरण केन्द्र घट्टा को पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत करने से दुग्ध उत्पादकों में दूध के विक्रय के लिए विश्वास बढ़ा है। इस दूध एकत्रिकरण केन्द्र में आधुनिक तकनीक के उपकरण स्थापित किये गये हैं तथा कम्प्यूटर के माध्यम से दूध की गुणवत्ता, दूध की मात्रा का उत्पादकों को मौके पर ही पता चल जाता है तथा दूध के मूल्य की कम्प्यूटरीकृत रसीद भी उन्हें उसी समय प्राप्त हो जाती है। दुग्ध एकत्रीकरण की घट्टा से प्रतिदिन 1200 लीटर दूध मिल्क फेडरेशन को प्रतिदिन विक्रय किया जा रहा है तथा उत्पादकों को कम्प्यूटर द्वारा दर्शाई गई दूध की गुणवत्ता के अनुसार 15 से 25 रुपये प्रति लीटर दूध के दाम दिये जा रहे हैं।

सफलता की कहानी

घट्टा दुग्ध उत्पादक सहकारी सभा का गठन जिस उद्देश्य से इस क्षेत्र में केवल 15 लोगों ने वर्ष 1986 में किया था, उस उद्देश्य में यह आज सफल हुए हैं तथा अब इस सभा की सदस्य संख्या लगभग 260 तक पहुंच गई है। मासिक तौर पर अगर देखें तो लगभग 36000 लीटर दूध और अगर वार्षिक तौर पर देखें तो लगभग 2,88,000 लीटर दूध इस केन्द्र के माध्यम से मिल्क फैडरेशन को विक्रय किया जा रहा है और अगर इस सभा से जुड़े दूध उत्पादक सदस्यों की औसतन मासिक आय आंकी जाये तो प्रति व्यक्ति 3000 रुपये कमा लेता है तथा वार्षिक आय 36 हजार रुपये बनती है। इसके साथ-साथ वार्षिक लाभांश का 12 प्रतिशत दुग्ध उत्पादकों को बोनस भी दिया जाता है। इस क्षेत्र के लोगों के लिए दुग्ध उत्पादन आय का अतिरिक्त साधन बना है जिससे इस क्षेत्र के गरीब लोगों विशेषकर गरीब महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। इस दुग्ध विक्रय केन्द्र के खुलने, सभा के उचित प्रबन्धन तथा प्रशासन द्वारा समय पर सहायता व प्रोत्साहित किये जाने से इस क्षेत्र के लोग दुग्ध उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हुए हैं। विशेषकर महिलाओं ने अच्छी नस्ल की गाय व भैंसे पालने को प्राथमिकता दी है। महिलाएं स्वयं दूध लेकर केन्द्र पर पहुंचती हैं तथा दूध का लेन-देन भी स्वयं करती देखी गई हैं। महिलाएं दुग्ध उत्पादन से हुई अतिरिक्त आय से आर्थिक तौर पर सुदृढ़ हुई हैं तथा अपने रोजमर्रा की आवश्यकताएं इसी आय से पूरी कर रही हैं।

घट्टा दुग्ध उत्पादक सहकारी सभा के प्रधान श्री रघुवीर सिंह ठाकुर ने बताया कि इस सभा का गठन 1986 में किया गया था। उस समय सभा के केवल 15 सदस्य थे जबकि वर्तमान में इस सभा के 260 सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र के लोगों में इस सभा के गठन के पश्चात दुग्ध उत्पादन में आकर्षण बढ़ा है क्योंकि सभा द्वारा दूध का उचित मूल्य समय पर दुग्ध उत्पादकों को दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार मिल्क फैड के माध्यम से प्रतिमाह सभा को सस्ती दरों पर दुग्ध उत्पादकों के लिए उचित मूल्य पर लगभग 40-50 क्विंटल पशु आहार उपलब्ध करवा रही है जबकि 40-50 किलो घी भी प्रतिमाह मिल्क फैड सभा को सस्ती दरों पर बेचने के लिए उपलब्ध करवाती है।

—कृष्ण चन्द चौहान

सरकार की अनूठी पहल

सीमेट्री टूरिज्म

जहां देश के विभिन्न राज्यों में पर्यटन को बढ़ाने के लिए नामचीन हस्तियों को ब्रांड अम्बेसडर बनाने की होड़ मची है, वहीं हिमाचल सरकार ने इस मामले में एक नयी सोच का सहारा लेने का फैसला किया है। इसके तहत राज्य में स्थित पुरानी कब्रगाहों को पर्यटन से जोड़ने का फैसला लिया गया है। यह अवधारणा न सिर्फ अनूठी है बल्कि यदि सिरे चढ़ गयी तो पर्यटन को नये आयाम भी देगी। पर्यटन सचिव श्रीमती मनीषा नंदा के मुताबिक इस योजना के तहत प्रदेश भर में मौजूद ब्रिटिशकालीन कब्रगाहों की हालत सुधारने के अलावा उनका तमाम विवरण जुटाया गया है। पूरा प्रोजैक्ट तीन चरणों में पूरा होगा। पहले परण में सभी कब्रगाहों की तमाम जानकारी जुटाई जायेगी। दूसरे में उन्हें कलमबद्ध किया जायेगा और नेट पर डाला जायेगा तथा तीसरे चरण में इस सारी जानकारी को खासतौर पर इंग्लैण्ड में प्रदर्शित करने की योजना है। पहले दो चरण लगभग पूर्ण हो चुके हैं और तीसरे चरण के तहत शीघ्र ही लंदन में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले में यह सूची प्रदर्शित की जायेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश में उपलब्ध अधिकांश कब्रें उन अंग्रेजों की हैं जो ब्रिटिशकाल में यहां रहने आये थे लेकिन किसी कारणवश यहीं मृत्यु हो गयी। उन लोगों के रिश्तेदार इंग्लैण्ड में रहते हैं जिन्हें सरकार हिमाचल आने के लिए प्रेरित करना चाहती है।

इन कब्रगाहों को एक पुस्तक के रूप में कलमबद्ध करने वाले लेखक राजा भसीन के मुताबिक मुख्य तौर पर हिमाचल में 15 कब्रगाहें हैं। इनमें चार शिमला में, दो डगशाई में स्थित हैं जबकि डलहौजी, नूरपुर, कसौली, पालमपुर और धर्मशाला में बड़े कब्रिस्तान स्थित हैं। सबसे पुराना

● संजीव शर्मा

कब्रिस्तान शिमला जिला के कोटगढ़ में हैं जो 1880 के आसपास का है। इन कब्रगाहों में एक मोटे अनुमान के अनुसार पांच हजार लोग दफन हैं जिनमें से कई नामचीन हस्तियां रही हैं। उदाहरण के लिए धर्मशाला के फर्स्ट गंज स्थित कब्रिस्तान में तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड एल्गिन की कब्र प्रमुख है। एल्गिन ने 1893 में यहीं अंतिम सांस ली थी। शिमला-कालका रेल मार्ग के मुख्य अभियंता एच.एस. हेरिंगटन भी शिमला में दफन हैं जबकि बहादुरशाह जफर के दरबार में बतौर रेजिडेंट नियुक्त रहे थॉमस मेटकाफ की पत्नी की कब्र भी शिमला में है।

समय के साथ हिमाचल की इन कब्रगाहों का स्वरूप बिगड़ता गया जिसे सुधार कर अब पर्यटन से जोड़ने की पहल की जा रही है। यह देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। सरकार के पर्यटन विभाग को इसके सफल रहने का पूरा भरोसा है। विभाग का मानना है कि इस कदम के बाद यूरोप से और ज्यादा संख्या में पर्यटक हिमाचल आयेंगे। उधर दक्षिण एशिया में कब्रगाहों की जिम्मेदार संस्था ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ सिमेटरीज इन साऊथ एशिया को भी विश्वास है कि यह योजना सौ फीसदी सफल होगी। संस्था की सचिव रोजी लवलीन जोन्स के मुताबिक यह उत्साहित करने वाला कदम है। हर सप्ताह हमें ब्रिटेन से ऐसे करीब डेढ़ सौ फोन आते हैं जिनमें लोग भारत में दफन अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी चाहते हैं। इसी तरह लंदन की जानी मानी ट्रेवल एजेंसी प्लेक्विन ट्रेवल की एजेंट मार्गरेट पारसी के अनुसार हर साल छह लाख ब्रिटिश सिर्फ इसलिए भारत आते हैं ताकि वहां जा सके जहां उनके पूर्वज दफन हैं। ये लोग ज्यादातर मेरठ, दिल्ली और हिमाचल जाते हैं। ऐसे में इस परियोजना की सफलता का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। जाहिर है जब पर्यटकों को इस बाबत सही जानकारी मिलेगी तो उनकी आमद तो बढ़ेगी ही।

औषधीय प्रदेश बनने की ओर अग्रसर

राज्य की बहुमूल्य वन सम्पदा के संरक्षण एवं संवर्द्धन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करने के उपरान्त हिमाचल प्रदेश में अब 'सांझा वन-संजीवनी वन' नामक वनीकरण की एक नवीन योजना आरम्भ की गई है। यह एक सामुदायिक योजना है। इस योजना के तहत प्रदेश में वृहद स्तर पर औषधीय पौधे लगाए जाएंगे।

राज्य सरकार ने हाल ही में इस महत्वाकांक्षी परियोजना को जन सहयोग से आरम्भ किया है। योजना के तहत प्रदेश के सभी व्यक्तियों को अपने-अपने आंगन में एक-एक औषधीय पौधा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बिगड़ते पर्यावरण को और लोगों का ध्यान आकर्षित करना है ताकि पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखा जा सके और लोगों के सहयोग से हिमाचल प्रदेश को औषधीय राज्य बनाया जा सके। देश के पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने और सामाजिक-आर्थिक विकास में वनों का महत्वपूर्ण योगदान है। वन न केवल रोजगार उपलब्ध करवाने का एक आवश्यक स्त्रोत हैं बल्कि वे हमें राजस्व एवं विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति भी करते हैं। 'इको सिस्टम' को संतुलित रखने में भी वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हिमाचल प्रदेश में लगभग एक लाख करोड़ रुपये की बहुमूल्य वन सम्पदा उपलब्ध है, जिसका संरक्षण न केवल प्रदेश के पर्यावरण के लिए बल्कि देश के पर्यावरण के लिए भी आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश में पौधों की लगभग 3500 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से करीबन 800 प्रजातियों का औषधीय महत्व है जबकि 165 प्रजातियां व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एकत्र की जाती हैं। हमारा राज्य देश में चिलगोज़ा, कुठ, 'डायोस्कोरिया', धूप, 'पिकरोरिज़्ज़ा', 'वेलोरियाना' तथा 'इफेडरा' का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।

राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को 'हर्बल स्टेट' बनाने के प्रति कृतसंकल्प है और इस योजना को सफल बनाने के उद्देश्य से पूरे राज्य में 525 संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों (जे.एफ.एम. सी) की सहायता से एक करोड़ से अधिक औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। इस वित्तीय वर्ष में यह समितियां विभिन्न पौधरोपण कार्यक्रमों के अन्तर्गत 2500 हैक्टेयर भूमि पर औषधीय पौधे लगाएंगी। बड़े होने पर इन पौधों से होने वाली आय का 75 प्रतिशत हिस्सा समिति को प्रदान किया जाएगा जबकि शेष 25 प्रतिशत राशि स्थानीय पंचायत को दी जाएगी।

इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम इन समितियों को औषधीय पौधों के विपणन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता करेगा। हाल ही में स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने पतांजलि योग पीठ हरिद्वार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि राज्य के औषधीय पौधों एवं जड़ी-बूटियों का उचित विपणन किया जा सके।

वन सम्पदा के संरक्षण एवं संवर्द्धन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करने के उपरान्त हिमाचल प्रदेश में अब 'सांझा वन-संजीवनी वन' नामक वनीकरण की एक नवीन योजना आरम्भ की गई है। यह एक सामुदायिक योजना है। इस योजना के तहत प्रदेश में वृहद स्तर पर औषधीय पौधे लगाए जाएंगे।

2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की 90 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर लकड़ी वन उत्पाद (नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स) अतिरिक्त आय का मुख्य साधन हैं। इन उत्पादों का संरक्षण एवं प्रबन्धन न केवल ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिकी को संबल प्रदान कर सकता है अपितु पर्यावरण के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। औषधीय पौधे तथा सुगन्धित फूल गैर लकड़ी वन उत्पाद प्रबन्धन का अहम हिस्सा हैं।

राज्य में पाए जाने वाले औषधीय पौधे तथा सुगन्धित फूलों से देश में औषधीय पौधों पर आधारित उद्योगों को 80 प्रतिशत कच्चे माल की आपूर्ति की जाती है। यदि इन उत्पादों का निर्यात किया जा सके तो इससे देश तथा प्रदेश को काफी लाभ मिल सकता है। औषधीय पौधे बेहद आसानी से उगाए जा सकते हैं और नकदी फसलों के रूप में इनसे अच्छी आय भी होती है।

प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबन्धन आम जन विशेषकर स्थानीय समुदायों के सहयोग के बिना सम्भव नहीं है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार वनों के संरक्षण एवं विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। समग्र वन प्रबन्धन के लिए कई नए कार्यक्रम एवं योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित बनाई जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में विश्व का सर्वश्रेष्ठ औषधीय पौधों का उत्पादक बनने की सम्भावनाएं हैं और 'सांझा वन-संजीवनी वन' नामक यह महत्वपूर्ण योजना राज्य का यह महत्वाकांक्षी सपना पूरा करने में मद्दगार साबित हो सकती है। इसके साथ ही यह योजना न केवल स्थानीय समुदायों को अतिरिक्त आय प्रदान करेगी बल्कि राज्य के वन क्षेत्र को बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होगी।

सूजसवि

मध्य हिमालयन परियोजना के तहत 550 ग्राम पंचायतों में कार्य आरम्भ

वन मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रदेश में 365 करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित की जा रही विश्व बैंक सहायता प्राप्त मध्य हिमालयन जलागम विकास परियोजना के तहत 5.20 लाख हेक्टेयर भूमि को उपचारित किया जा रहा है जिसके तहत प्रदेश में अब तक 550 ग्राम पंचायतों में कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

श्री नड्डा ने यह जानकारी गत दिनों शिमला में मध्य हिमालयन जलागम विकास परियोजना की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए दी। श्री नड्डा ने कहा कि राज्य के 10 जिलों के 42 विकास खण्डों की 602 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित की जा रही इस परियोजना के तहत राज्य में वर्ष 2008-2009 तक 140.30 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। इस राशि में से संस्थागत सुदृढ़ीकरण पर 17.53 करोड़, जलागम विकास एवं प्रबन्धन के अन्तर्गत 90.94 करोड़, आजीविका वर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत 3.83 करोड़ तथा परियोजना समन्वय पर 27.94 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

वन मंत्री ने कहा कि परियोजना को जलागम पद्धति के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों के सतत् विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त एवं सुदृढ़ करने तथा वास्तव में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करके विकास प्रक्रिया में जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये ग्राम पंचायतों को ग्रांट-इन-एड (GIA) के रूप में 33.52 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए गए हैं। सहभागिता के आधार पर लाभार्थी अंश के रूप में प्राप्त 6.59 करोड़ रुपये ग्राम पंचायतों में रख-रखाव व सम्बद्ध गतिविधियों पर व्यय किए जाएंगे।

- परियोजना लागत 365 करोड़
- 141 करोड़ व्यय
- 1784 स्वयं सहायता समूह व 2134 उपभोक्ता समूह गठित

वन मंत्री ने कहा कि परियोजना को ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है तथा आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, महिलाओं, भूमिहीन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति समुदायों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रशिक्षण व आर्थिक सहायता द्वारा सशक्त बनाया जा रहा है।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अब तक 1784 स्वंय सहायता समूह एवं 2134 उपभोगता समूह गठित किये गये हैं। मुख्य परियोजना निदेशक श्री आर0 के0 कपूर ने परियोजना की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस परियोजना के तहत शेष पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा।

गृह निर्माण के लिए 93 परिवारों को धनराशि प्रदान

मुख्य संसदीय सचिव (ऊर्जा एवं युवा सेवाएं) श्री सतपाल सिंह सत्ती ने गत दिनों ऊना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उपमंडल स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला में 93 गरीब परिवारों को गृह निर्माण के लिए 28.52 लाख की राशि वितरित की। इसके अलावा उन्होंने अपंग विवाह अनुदान के रूप में 7 लाभार्थियों को 53 हजार रुपये, अंतर्जातीय विवाह के एक लाभार्थी को 25 हजार रुपये और महिला स्वयं रोजगार योजना के तहत 2 लाभार्थियों को पांच हजार रुपये की राशि भी प्रदान की। इस कार्यशाला का आयोजन नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (1195) तथा अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989) के तहत किया गया। श्री सत्ती ने इस अवसर पर कहा कि जिला ऊना में चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 6.76 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

हरलोग में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

विकास खण्ड घुमारवीं के तहत हरलोग में गत दिनों विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता राजेश चौहान अध्यक्ष, उपमण्डल स्तरीय विधिक सेवा समिति एवं न्यायिक जज जूनियर डिवीजन घुमारवीं ने की। शिविर में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए नि:शुल्क विधिक सेवा तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों व पंचायत की न्यायिक शक्तियों के बारे में कानूनी जानकारी प्रदान की गई। इस शिविर में ग्राम पंचायत सरयूण चलैली, रोहिण, हरलोग, हवाण तथा कुहमझवाड़ के पंचायत प्रतिनिधियों, स्थानीय महिला मण्डल व लोगों सहित 100 लोगों ने कानून की जानकारी हासिल की।

श्री राजेश चौहान ने कहा कि जिन लोगों की सालाना आय 50 हजार रू0 से कम है वे निशुल्क कानूनी सहायता के पात्र होते हैं, साथ ही अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व असहाय व्यक्ति, महिलाएं, अपंग अथवा आपदा पीड़ित व्यक्ति, औद्योगिक मजदूर तथा विचाराधीन कैदी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को एक सादे कागज पर प्रार्थना पत्र देकर नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि पंचायतों को जो न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं उनका प्रयोग करते हुए छोटे-मोटे मामले न्यायलय में न भेजकर अपने स्तर पर ही इन्हें निपटाएं। उन्होंने कहा कि इससे लोगों के धन व समय दोनों की बचत होगी।

मुख्य मंत्री द्वारा अग्निकांड पर दु:ख व्यक्त

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने गत दिनों शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल के अंतर्गत खड़ापत्थर के समीप गंगानगर-शीलघाट गांव में आग की घटना पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है, जिसमें कई मकान जलकर राख हो गये। मुख्य मंत्री ने जिला प्रशासन को अग्निकांड से प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता एवं राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों का पुनर्वास शीघ्र सुनिश्चित बनाने के भी निर्देश दिए।

मुख्य मंत्री कांगड़ा जिले के नूरपुर उपमंडल के काठगढ़ में महाराणा प्रताप की जयंती पर आयोजित राज्यस्तरीय समारोह के अवसर पर

काठगढ़ में बनेगा महाराणा प्रताप भवन

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि प्रदेश सरकार महान योद्धाओं से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं तथा महान योद्धाओं से संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन में अपना पूर्ण सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले के काठगढ़ में महाराणा प्रताप भवन के निर्माण किया जाएगा। उन्होंने इसके निर्माण कार्य को आरंभ करने के लिए 11 लाख रुपये का अनुदान देने की घोषणा की। मुख्य मंत्री गत दिनों कांगड़ा जिले के नूरपुर उपमंडल के काठगढ़ में राजपूत कल्याण सभा द्वारा महान योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती पर आयोजित राज्यस्तरीय समारोह 'महाराणा प्रताप आदर्श सम्मेलन' के अवसर पर बोल रहे थे। मुख्य मंत्री ने राज्य में, विशेष तौर पर प्रदेश के सीमावर्ती ज़िलों में कन्या जन्म दर में आ रही गिरावट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे समाजिक अस्थिरता उत्पन्न होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि एक शिक्षित महिला पूरे परिवार को शिक्षित करती है, जबकि एक शिक्षित पुरुष केवल एक व्यक्ति को ही शिक्षित कर सकता है। उन्होंने लोगों से उनके संबंधित क्षेत्रों में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने तथा ऐसी किसी भी घटना की सूचना स्थानीय अधिकारियों को देने की अपील की।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस तरह की गतिविधियों में सहयोग के लिए व्यक्ति विशेष के अतिरिक्त पंचायतों को अतिरिक्त विकासात्मक अनुदान देकर सम्मानित किया जाएगा, जबकि इन गतिविधियों को रोकने के लिए सूचना देने वाले को नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उन्होंने समाज में महिलाओं को उचित सम्मान देने की

- मुख्य मंत्री ने की जिले में कन्या जन्म दर में आ रही गिरावट पर चिंता व्यक्त
- महाराणा प्रताप भवन के निर्माण के लिए 11 लाख का अनुदान

प्रदेश सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुए कहा कि आगामी पंचायती राज चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी, ताकि लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित बनाया जा सके।

प्रो. धूमल ने कहा कि समाज के लिए आदर्श एवं उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले महान व्यक्तियों को इतिहास हमेशा याद रखता है। महाराणा प्रताप ने राजसी जीवन की हर सुख-सुविधा का परित्याग कर साधारण जीवन अपनाया तथा उनके परिवारजनों को अन्न न मिलने पर घास तक खाने के लिए बाध्य होना पड़ा। बावजूद इसके उन्होंने अकबर के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा तथा देशहित में कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पौंग बांध का नामकरण महाराणा प्रताप सागर कर इस महान योद्धा को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रो. धूमल ने इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए 21,000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा की।

मुख्य मंत्री ने इस अवसर पर ऑडियो कैसेट् तथा श्री सन्नी सलारिया द्वारा निर्मित सी.डी 'तलवार' का विमोचन किया। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री श्री रविन्द्र सिंह रवि ने कहा कि महाराणा प्रताप ने अपना सम्पूर्ण जीवन समाज के उत्थान में समर्पित किया तथा उनकी शिक्षाएं आज के परिप्रेक्ष्य में भी प्रासंगिक हैं।

सांसद डॉ. राजन सुशांत, विधायक सर्वश्री राकेश पठानिया एवं देशराज, पूर्व सांसद श्री कृपाल परमार, पूर्व विधायक सर्वश्री डॉ. हरबंस राणा व विक्रम कटोच भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

नेरी-बुधान में पशु औषधालय का लोकार्पण

मुख्य संसदीय सचिव (लोक निर्माण व उच्च शिक्षा) श्री वीरेन्द्र कंवर ने गत दिनों कुटलैहड़ विधान सभा क्षेत्र के नेरी-बुधान में 6.34 लाख की लागत से निर्मित पशु औषधालय का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर बुधान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री कंवर ने कहा कि कुटलैहड़ में सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। ऊना से लठियानी-बड़सर तक सड़क के स्तरोन्त कार्य पर करीब 100 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि लठियानी-कोडरा सड़क को भी शीघ्र स्तरोन्नत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोडरा से तूतड़ू तक 13 करोड़ रुपये की पेयजल योजना क्रियान्वित की जा रही है।

श्री कंवर ने इस अवसर पर नेरी और बुधान में सामुदायिक भवनों के लिए डेढ़-डेढ़ लाख रुपये देने की घोषणा की।

सिरमौर जिले में सड़कों के निर्माण व रख-रखाव के लिए 122 करोड़

लोक निर्माण तथा राजस्व मंत्री ठाकुर गुलाब सिंह ने बताया कि ज़िला सिरमौर में सड़कों के निर्माण व रख-रखाव पर इस वर्ष 122 करोड़ रुपये व्यय किए जायेंगे। वह गत दिनों बनेठी पंचायत के चुंजर जोहड़ी में लोक निर्माण विभाग द्वारा आयोजित विशेष पौधरोपण अभियान के पश्चात् एक जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा इस अभियान के तहत् इस वर्ष तीन लाख सजावटी व छायादार पौधे सड़कों के किनारे लगाए जायेंगे। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा ज़िला कांगड़ा के पालमपुर के निकट परोर में एक नर्सरी तैयार की जाएगी जिसके माध्यम से 80 बीघे जमीन पर सजावटी व छायादार पौधे लगाए जायेंगे। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि कुम्हारहट्टी-नाहन सड़क को 'हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजना' के तहत् लाया जाएगा तथा इस पर कार्य शीघ्र आरम्भ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1365.435 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत

- तीन लाख सजावटी व छायादार पौधे सड़कों के किनारे लगाए जायेंगे।
- कुमारहट्टी-नाहन सड़क का कार्य शीघ्र आरम्भ

435 किलोमीटर लम्बे उच्च मार्गों तथा जिलों की प्रमुख सड़कों को स्तरोन्नत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत् प्रदेश की 2000 किलोमीटर लम्बी सड़कों का आवधिक रख-रखाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष ज़िला में अभी तक 14 किलोमीटर मोटर योग्य मार्ग, छ: किलोमीटर सड़कों पर रोड़ी डाली गई, 16 किलोमीटर सड़कों की वियरिंग, 40 किलोमीटर पर टारिंग तथा 21 किलोमीटर पर नवीकरण कोट भी डाले गए तथा 28 किलोमीटर सड़कों पर पुलिया बनाई गई। ठाकुर गुलाब सिंह ने चुंजर जोहड़ी से श्यामला, गोंत तथा कटोरड़ गांवों के लिए सड़कों के निर्माण का भी आश्वासन दिया। पूर्व मंत्री सुश्री श्यामा शर्मा ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में अभूतपूर्व विकास हो रहा है तथा समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए विकासात्मक योजनाएं चलाई जा रही हैं।

मुख्य संसदीय सचिव चौधरी सुखराम भी उपस्थित थे।

विशेष घटक योजना के तहत डीटीएच का वितरण

शिक्षा मंत्री श्री आईडी धीमान ने गत दिनों हमीरपुर जिले के भोरंज में आयोजित किसान मेला के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विशेष घटक योजना के तहत सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के तत्वावधान में आईसीसी के अंतर्गत भोरंज विकास खण्ड के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पात्र 35 व्यक्तियों को डीटीएच बांटे।

शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर कृषि विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय किसान मेला की अध्यक्षता करते हुए किसानों से राज्य सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का पूरा लाभ उठाने का आह्वान किया।

हिमाचल की प्रगति और संस्कृति का दर्पण
गिरिराज

दूसरों को खुश देखकर यह नहीं समझना चाहिए कि उसे कोई दुख नहीं है। *-अज्ञात*

ग्राम सभा बैठकें

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति व गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों तथा लघु एवं सीमांत किसानों की निजी भूमि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए छः सितम्बर को पूरे प्रदेश में ग्राम सभा की विशेष बैठकें आयोजित की जा रही है। इन बैठकों में अधिक से अधिक क्षेत्र को सिंचाई के तहत लाने के लिए कार्य योजनाओं को मंजूरी प्रदान की जाएगी। ग्राम पंचायतों में होने वाली ग्राम सभाओं की बैठकों में जनता को अपनी भागीदारी सुनिश्चित बनानी चाहिए ताकि गांवों का सर्वांगीण विकास हो सके। ग्राम सभा की बैठक में अधिक से अधिक लोग भाग लें, ऐसा सरकार का प्रयास रहता है। इसमें दो राय नहीं कि प्रदेश की वर्तमान सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल की तर्ज पर इस बार भी ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के प्रयास शुरुआत से ही प्रारंभ कर रखे हैं। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को व्यापक शक्तियां प्रदान की जा रही है। अनेक अन्य शक्तियों का हस्तांतरण पंचायती राज संस्थाओं को किया जा रहा है। ग्राम सभा की बैठकों में स्थानीय लोगों को प्रत्येक कार्य में विश्वास में लिया जाता है। हिमाचल में ग्राम सभाओं की बैठकों को आयोजित करना अनिवार्य बनाया गया है। इन बैठकों में स्थानीय क्षेत्रों की विकासात्मक जरूरतों तथा अन्य समस्याओं पर विचार विमर्श की प्राथमिकताएं भी तय की जाती है। वास्तव में हिमाचल में पंचायतें राज्य शासन की एक आधारभूत प्रशासकीय इकाई बन गई हैं। पंचायतें अपने इलाकों में जनहित के सभी कार्यों को सरंजाम दे रही हैं। वर्तमान सरकार के सत्ता संभालने के बाद से ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। पंचायतें भी अपने क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं को तय कर अमलीजामा पहना रही हैं। यह जरूरी भी है कि स्थानीय लोगों की प्राथमिकताओं के अनुसार रोजगार योजनाएं व विकास योजनाएं तय की जाएं। गांव-गांव स्वरोजगार उपलब्ध करवाने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। ज्यादातर योजनाओं को पंचायतों के माध्यम से चलाया जा रहा है। सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने तथा इन संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन की स्वावलम्बी इकाई बनाना चाहती है। हिमाचल की वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में पंचायती राज संस्थाओं को समय-समय पर जो शक्तियां हस्तांतरित की उससे प्रजातंत्र की यह मूल इकाइयां सशक्त हुई है साथ ही निचले स्तर से विकास की प्रक्रिया भी तेज हुई। सरकार अपने उद्देश्य में सफल हुई और पूरे प्रदेश में विकास को नई दिशा भी मिली है। पंचायती राज संस्थाओं को जीवन्त बनाने तथा इन संस्थाओं में कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1993 में संविधान में 73वां संशोधन किया गया। हिमाचल प्रदेश देश के उन राज्यों में से एक है जिसने संवैधानिक संशोधन की भावना के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने तथा इन संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन की कारगर इकाई बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय अधिकार प्रदान किये। निर्वाचित पदाधिकारियों के मानदेय दरों में सम्मानजनक बढ़ोतरी की गई। ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने में ग्राम सभा बैठकें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। ग्रामीणों का दायित्व बनता है कि वे इन बैठकों को सफल बनाने के लिए इनमें अवश्य भाग लें।

जलवायु परिवर्तन के प्रमुख घटक

जन राय

» डॉ. वी.के. शर्मा

प्रकृति से छेड़छाड़ करना मानव के सभ्य होने की सूचक है। अति प्राचीन काल में मानव प्रकृति से छेड़खानी तो करता था लेकिन प्रकृति स्वयं ही उसछेड़छाड़ को सहन कर उससे हुई हानि की भरपाई अथवा मरम्मत कर लेती थी जिससे प्रकृति में संतुलन बना रहा। आरम्भिक काल में मानव को अपनी तीन आधारभूत जरूरतों-भोजन (पेट भरने के लिए), कपड़ा (तन ढांपने के लिए) और आश्रय (रहने के लिए) के लिए ऐसा कुछ चाहिए था जिसे वह सफलता से प्राप्त कर संतुष्ट भी था। धीरे-धीरे विकास या उन्नति का उसे आभास हुआ, उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन शुरू हो गया। रूखे सूखे भोजन के स्थान पर अच्छा भोजन, कपड़े के नाम पर बढ़िया रंग और गुणवत्ता वाला कपड़ा और निवास के लिए एक आलीशान भवन जिसमें सभी आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके साथ ही इसे यातायात के लिए एक आरामदेह सवारी चाहिए। इन सभी को प्राप्त कर उसे लालसा, घमण्ड, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि का बोध हुआ जिसका सीधा प्रभाव प्रकृति पर पड़ा।

जरूरतें बढ़ने के कारण विभिन्न प्रकार के अन्न और अन्य भोज्य सामग्री के लिए कृषि पर निर्भर होना पड़ा। भू-व्यवस्था में सुधार के नाम उसका क्षेत्रफल बढ़ाया जिससे वनों का कटान शुरू हो गया।

कृषि उत्पाद को बढ़ाने के लिए रासायनिक विधियां अपनानी शुरू हो गई। कृत्रिम खाद, कीटनाशक और अन्य प्रकार के रसायनों ने प्राकृतिक खाद और कीटनाशक उपायों का स्थान तो ले लिया। लेकिन इन कृत्रिम खाद, कीटनाशक, खरपतवारनाशक, कृत्रिम वृद्धि नियामकों और अन्य रसायनों का कुप्रभाव भूमि, फसलों, पशुओं, पक्षियों और उस पर प्रभावित समाज पर पड़ने लगा। भूमि की उर्वरा शक्ति में ह्रास, खनिज पदार्थों की मात्रा में असंतुलन और पेड़-पौधों में इन रसायनों के अवशेष होने के कारण भूमि और उत्पाद के उपयोग करने वालों पर हानिकारक प्रभाव पड़ने लगे। मनुष्य तथा अन्य जीवधारियों पर नाना प्रकार के रोगों और कष्टों का आक्रमण बढ़ गया। अंततः भू-व्यवस्था में परिवर्तन होने के कारण स्थानीय वातावरण पर प्रभाव पड़ा, जो बढ़कर जलवायु परिवर्तन का एक मुख्य संघटक बन गया।

निवास और अन्य आवश्यकताओं के लिए वनों का कटान शुरू हुआ। प्रारम्भिक स्तर पर केवल कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए वनों को काटा गया पर बाद में गृह निर्माण तथा अन्य कार्यों के लिए जहां लकड़ी की आवश्यकता थी वनों पर कुल्हाड़ी चली। निर्माण के लिए मिट्टी के स्थान पर लकड़ी का चयन किया ताकि निवास चिरस्थायी रहे। बाद में लकड़ी की कमी होने पर सीमेंट और लोहे का प्रयोग बढ़ा। वन कटान के बाद पेड़ लगे नहीं परन्तु वहां सीमेंट के कंकरीट जंगल तैयार हो गये। पेड़ों ने जिनमें वातावरण के तापक्रम को संतुलित रखने की क्षमता थी, के अभाव में तापक्रम में बढ़ोतरी शुरू हो गई। रही सही कसर सीमेंट ने कर दी। दिन अति गर्म और रात्रि अति ठण्डी। इन भवनों में तापक्रम को बनाये रखने के लिए ईंधन का प्रयोग शुरू हुआ और आज उस ईंधन का स्थान बिजली ने ले लिया है। भवनों को वातानुकूलित करने के लिए ऊर्जा का निरंतर उपयोग बढ़ रहा है। जल विद्युत उत्पादन का प्रथम स्थान रहा है परन्तु इसके स्थान पर कोयला तथा थर्मल और अब तो अणु का प्रयोग हो रहा है। ये सभी जलवायु परिवर्तन के प्रमुख घटक हैं।

डीजल, पेट्रोल तथा अन्य पदार्थों के जलने पर ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए नये यंत्रों का निर्माण किया गया। इनके जलने या उपयोग के परिणामस्वरूप वातवरण में कुछ ऐसी गैसें पैदा हो रही है जो सभी जीवधारियों के लिए घातक है। ये खनिजों को भी हानि पहुंचाती है। उद्योगों से कई प्रकार के पदार्थ, ठोस, तरल और गैस रूप में उत्सर्जित होते हैं। ये सभी लाभदायक न होकर हानि करते हैं। पर्यावरण को दूषित करने के स्थान पर ये वातावरण को गर्म रखने में अधिक सहायक होते हैं जिसके परिणामस्वरूप ये वातावरण में जलवायु परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी हैं।

उन्नीसवीं शताब्दी से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला है। बढ़ती जनसंख्या को कम और अधिक धन प्राप्त करवाने के लिए इस व्यवसाय को औद्योगिक क्रांति का नाम दिया। आज सभी देशों में चाहे विकसित हों या विकासशील, सभी में औद्योगिकीकरण पर अधिक बल दिया जा रहा है। जनता गांव से कृषि व अन्य सम्बन्धित व्यवसाय छोड़कर शहरों के उद्योगों में नौकरी पाने के लिए उमड़ रही है। गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ने के कारण शहरों के विस्तार से भूमि पर दवाब बढ़ा है।

ऐसा माना जाता है कि हरित गृह उत्पादन विधि एक सरल, उपयोगी और लाभदायक विधि है। सामान्य कृषि विधि से उपज अधिक तथा अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। यदि हम थोड़ा परिश्रम करें और धन लगाये तो किसी भी ऋतु में कोई भी फसल प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हरित गृह प्रणाली में पौधों के लिए वातावरण को नियंत्रण में रखने की पूरी सुविधा है। अधिक और असमय उपज के लिए हरित गृह प्रणाली एक वरदान के समान है। परन्तु इससे उत्सर्जित गैसें और बाद में प्रयोग में लाई गई भूमि का सुधार करना एक बड़ी विकट समस्या है।

ऐसा माना जाता है कि हरित गृह उत्पादन विधि एक सरल, उपयोगी और लाभदायक विधि है। सामान्य कृषि विधि से उपज अधिक तथा अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। यदि हम थोड़ा परिश्रम करें और धन लगाये तो किसी भी ऋतु में कोई भी फसल प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हरित गृह प्रणाली में पौधों के लिए वातावरण को नियंत्रण में रखने की पूरी सुविधा है। अधिक और असमय उपज के लिए हरित गृह प्रणाली एक वरदान के समान है।

जलवायु परिवर्तन के कारण अत्याधिक और अप्रत्याशित रूप में वर्षा का होना और लम्बे समय तक सूखा पड़ना हानिकारक है। इन दोनों के परिणामस्वरूप भूमि का क्षरण चाहे वह जल से हो या वायु से दोनों में बढ़ोतरी हो जाती है। समुद्रतल के पास के क्षेत्रों में विशेष प्रकार के उतार चढ़ाव प्रायः देखे जाते हैं। ऊंची लहर के कारण लाखों किलोमीटर का क्षेत्र प्रभावित होता है। चक्रवातों की अधिकता एक अन्य समस्या है। समुद्र तल पर बसे कुछ क्षेत्र जल मग्न हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि अगले 50 वर्ष में कुछ द्वीप जलमग्न हो जायेंगे और उनका अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।

जलवायु परिवर्तन होना कोई नई बात नहीं है। ज्यों ज्यों हम प्रगति कर रहे हैं। ऊर्जा के अधिक उत्पादन व प्रयोग के कारण समस्त भूमण्डल पर तापक्रम में बढ़ोतरी हो रही है। यह बढ़ोतरी विकास या प्रगति की गति के साथ जुड़ी है। मानव की दिनोंदिन बढ़ती आवश्यकताओं की मांग की पूर्ति के लिये गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है। इसमें प्रमुख हरित गृह गैसें हैं। इन गैसों का उचित प्रयोग नहीं हो पा रहा है। गैस अधिक मात्रा में बढ़ रही है। सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइआक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। अन्य गैसें हैं-मिथेन, नाइट्रिस आक्साईड, सल्फर डाईआक्साईड आदि।

गैसों के बढ़ने के कारण वातावरण के निचले सार पर ऊर्जा का सार बढ़ा देता है। इसलिये वहां का तापमान बढ़ जाता है। लगभग एक शताब्दी में तापक्रम में 0.7 डिग्री सें. की वृद्धि पाई गई है। वर्तमान समय को परिवर्तन के लिए सामान्य माना जाये तो अगली शताब्दी तक यह आंकड़ा 1.4 डिग्री सें. तक पहुंच सकता है।

जलवायु परिवर्तन का अधिक प्रभाव उष्ण क्षेत्रीय जलवायु वाले स्थानों पर होगा जबकि शीत जलवायु के क्षेत्र में कम। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव फसल उत्पादन, मृदा, पशुधन, कीट-व्याधियों और वनों में आग पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। बाढ़ और सूखे के कारण अकाल, निर्धनता, लूटपाट जैसी विकराल परिस्थितियां पहले भी देखी जा चुकी हैं। हो सकता है यह और उग्र रूप धारण कर ले।

मोटे तौर पर देखा जाये तो पता चलता है कि विकसित देश ही जलवायु परिवर्तन की गति को बढ़ाने वाले हैं। इन देशों के पास प्राकृतिक स्रोतों के असीम भण्डार हैं और वह इनका उपयोग बहुत कम करते हैं।

जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए मुख्य बिन्दु:-

-पेड़-पौधों को अधिक से अधिक रोपना।

-वनस्पति क्षेत्र में वृद्धि के लिए वनों तथा अन्य कृषि क्षेत्रों में उचित फसलों का चलन।

-प्राकृतिक स्रोतों का सही उपयोग।

-जल का विवेकपूर्ण प्रयोग।

-नदी नालों, कूहलों तथा अन्य जलवाहकों का प्राकृतिक स्वरूप बनाये रखना।

-वायु शुद्धता को बनाये रखना।

-ऊर्जा का सही उपयोग करना।

इन सभी कार्यों को मिलजुलकर सामाजिक दायित्व के साथ करने की आवश्यकता है। एक-एक पग चलकर हम पूरा मार्ग तय कर सकते हैं। हर कदम सोच-समझकर उठायें और यह सब योजनाबद्ध ढंग से होना चाहिए। समस्या जटिल है पर असाध्य नहीं है। इस पर विजय पाना सरल न होकर थोड़ा कठिन है।

अतः आओ मिलकर अपना योगदान दें ताकि आने वाली पीढ़ियां सुखी रहें।

जन संसद जन संसद

हैण्ड पम्प लगाने का आग्रह

मैं गिरिराज के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार का ध्यान जिला बिलासपुर के पिछड़ा क्षेत्र कोटधार की ग्राम पंचायत पपलोआ विकास खण्ड झण्डुता की ओर दिलाना चाहता हूं। कोट गांव की लगभग 650 जनसंख्या है। इस गांव में पानी का कोई भी स्रोत नहीं है। सूखे के कारण जो भी जल स्रोत हैं वे सब सूख गये हैं। गांव में पानी पांच से छह दिन बाद आता है।

अतः सिंचाई मंत्री तथा जिला प्रशासन से अनुरोध है कि गांव की पेयजल समस्या को देखते हुए यहां हैण्डपम्प लगाने के निर्देश दें।

झण्डुता सुभाष चन्द ठाकुर

कांगड़ा जिला

99 प्रतिशत पंचायतें सड़कों से जुड़ीं

सड़कें विकास की भाग्य रेखाएं हैं। वर्तमान सरकार सड़क निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है तथा इस कड़ी में कांगड़ा जिला में सरकार द्वारा सड़कों का जाल बिछाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। जिला की कुल 760 पंचायतों में से जुलाई, 2009 तक 751 पंचायतों को सड़क सुविधा से जोड़ दिया गया है जोकि 9881 प्रतिशत उपलब्धि दर्शाता है। इसके अलावा 500 से अधिक आबादी वाले 740 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें संचार का एक मात्र माध्यम है जिसके बिना किसी भी क्षेत्र के चहुंमुखी विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सड़कों के पहुंचने से क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक- आर्थिक स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है।

प्रशासनिक एवं आवादी की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा 5739 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जिसकी वर्ष 2001 की जनगणना के मुताबिक 11,74,072 आबादी 3,869 गांवों में रहती है। जिला को प्रशासनिक दृष्टि से आठ उपमंडल तथा विकास की दृष्टि से 15 विकास खण्ड एवं 760 ग्राम पंचायतों में विभाजित किया गया है।

जिला में जुलाई 2009 तक सड़कों की कुल लम्बाई लगभग 5,500 किलोमीटर है जिसमें 4,000 से अधिक किलोमीटर सड़कें पक्की हैं। जिला में चालू वित्त वर्ष के दौरान सड़कों एंव पुलों के निर्माण पर 121 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा रही है जिसके अन्तर्गत 91 किलोमीटर नई वाहन योग्य सड़कों के निर्माण के अतिरिक्त 18 पुलों एंव 55 गांव को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है इसके अतिरिक्त चालू वित्त वर्ष में 297 किलोमीटर सडकों में क्रॉस ड्रेनेज, 153 किलोमीटर सड़कों में सोलिंग, 183 किलोमीटर सड़कों में टारिंग तथा 368 किलोमीटर सड़कों पर तारकोल बिछाया जायेगा।

केंद्र सरकार द्वारा सीआरएफ योजना के तहत कांगड़ा जिला के लिये 20 करोड रुपये की चार योजनायें स्वीकृत की गई हैं जिसमें 392 करोड रुपये की राशि धर्मशाला शहर के बाई पास का निर्माण, 383 करोड रुपये से चैतड़ू-शीला-दाड़ी सड़क का सुधार व उड्डयन, 643 करोड रुपये की राशि से कांगडा टांडा सड़क एंव सुक्कड़ खड्ड पर निर्मित किये जाने वाले पुल तथा 588 करोड़ रुपये की राशि से कलोहा-प्रागपुर- नैहरनपुखर सड़क के सुधार एंव उड्डयन हेतु स्वीकृत की गई है।

कांगड़ा जिला में चालू वित्त वर्ष के दौरान नाबार्ड के अर्न्तगत 22 करोड़ रुपये की राशि से तीन परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं जिसमें 1745 करोड़ रुपये की राशि से ज्वालामुखी-चंबा पत्तन सड़क के ब्यास नदी पर पुल के निर्माण हेतु 188 करोड़ रुपये की राशि रिड़ कुमार से गतारड़ा सम्पर्क सड़क तथा 267 करोड़ की राशि रोपडी-कटोचन गांव के सम्पर्क सड़क के निर्माण पर व्यय की जायेगी। इसी प्रकार भारत निर्माण कार्यक्रम के अर्न्तगत 269 करोड़ की राशि भरवाई से करोआ कलां सड़क के निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये हैं।

जिला की दो सड़कों के स्तरोन्नत करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से 8727 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें रानीताल-कोटला सड़क के स्तरोन्नत करने पर 4622 करोड़ रुपये और भवारना-लम्बागांव सड़क के स्तरोन्नत करने पर 4105 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त गगल से धर्मशाला तक की सड़क को सुपर हाइवे बनाये जाने की योजना है।

विभाग द्वारा सड़कों के किनारे पौधरोपण का कार्यक्रम भी आरंभ किया गया है जिसके अर्न्तगत गत वित्त वर्ष में कांगड़ा जिला में 25660 पौधे रोपित किये गये जबकि चालू वित्त वर्ष में 40 हजार पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है।

–बाबू राम चौहान

सामाजिक उत्थान की दिशा में पहल

प्रदेश सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को शीघ्र सामाजिक आर्थिक उत्थान के प्रति वचनबद्ध है तथा इन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। शिमला जिले के विकास खण्ड रामपुर के अंतर्गत चलाई जा रही अनेक योजनाओं का लाभ इन परिवारों को मिला है। विगत वर्ष अटल आवास योजना के अंतर्गत 24 अनुसूचित जाति के और 17 अन्य लोगों को कुल 41 व्यक्तियों को उन्हें 38,500 रुपये नये मकान बनाने के लिए अनुदान स्वरूप राशि वितरित की गई जिन पर 16 लाख रुपये व्यय हुए। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत छः व्यक्तियों को 27,500 रुपये के हिसाब से व 42 व्यक्तियों को 38,500 रुपये के हिसाब से मकान बनाने के लिए यह राशि अनुदान स्वरूप दी गई जिन पर कुल 18 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

नरेगा के तहत 1.34 करोड़ रुपये व्यय किये गये जिसके अंतर्गत 5,362 परिवारों को रोजगार प्रदान कर 1,61,299 कार्य दिवस अर्जित किये गये।

राष्ट्रीय परिवार योजना के अंतर्गत प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाने पर 10 हजार रुपये प्रति परिवार के हिसाब से 20 व्यक्तियों को दो लाख रुपये की राशि अनुदान स्वरूप वितरित की गई। मातृ शक्ति बीमा योजना के अंतर्गत छः परिवारों को तीन लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 24 स्वयं सहायता समूहों को व 31 परिवारों को स्वर्ण जयंती व्यक्तिगत योजना के तहत कुल ऋण 61.33 लाख रुपये दिया गया जिस पर 17.71 लाख रुपये की राशि अनुदान स्वरूप वितरित की गई। हरियाली योजना के अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षण, प्रशासनिक व्यय, स्वयं सहायता समूहों अन्य कार्यों जैसे पॉली टैंक बनाना, कच्चे तालाब, कूहल चैक डैम बनाना और पौधे लगाना इत्यादि कार्य किये गये जिन पर 54 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) के तहत 1.34 करोड़ रुपये व्यय किये गये जिसके अंतर्गत 5,362 परिवारों को रोजगार प्रदान कर 1,61,299 कार्य दिवस अर्जित किये गये। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत प्रत्येक गांव से स्वयं सहायता समूहों का गठन करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

–इन्द्र सिंह चन्देल

पशुपालकों के लिए उपयोगी हरा चारा

कृषक मित्र

हिमाचल प्रदेश के अधिकतर किसान छोटे किसान है, जिनके पास बहुत ही कम जमीन है जिसमें वे सब्जियां, अनाजय फसलें या दालें व तेल वाली फसलें उगाते हैं। बहुत कम किसानों के पास ही चारे की फसलें उगाने के लिए जमीन उपलब्ध है। यदि घासनियां हैं तो वे भी कांटेदार झाड़ियों व अन्य पेड़-पौधों से भरी पड़ी हैं जिनके पत्तों को दुधारू पशु नहीं खाते हैं।

हरा चारा पशुओं के लिए ही नहीं, पशुपालकों के लिए भी वरदान है। पशुओं को यह जहां ऊर्जा, विटामिन, प्रोटीन व खनिज उपलब्ध करवाता है, वहां पशुपालकों को पशुओं को खरीदकर फीड नहीं देनी पड़ती है जिससे कि पशुओं के पालने पर कम खर्च करना पड़ता है। पशुओं के पालने का 70 प्रतिशत खर्चा क्रय की गई फीड पर ही आता है। यदि अच्छा व उत्तम हरा चारा उपलब्ध हो तो यह खर्चा कम किया जा सकता है। यदि हरा चारा जरा भी उपलब्ध न हो तो एक तो दूध उत्पादन कम हो जाता है दूसरा पशुओं के रखरखाव पर खर्चा भी बढ़ जाता है।

हरा चारा पशुओं के लिए ही नहीं, पशुपालकों के लिए भी वरदान है। पशुओं को यह जहां ऊर्जा, विटामिन, प्रोटीन व खनिज उपलब्ध करवाता है, वहां पशुपालकों को पशुओं को खरीदकर फीड नहीं देनी पड़ती है जिससे कि पशुओं के पालने पर कम खर्च करना पड़ता है।

एनबी-37 (नेपियर बाजरा) हाईब्रिड-यह वनस्पति विधि द्वारा तैयार अधिक उपज देने वाली बहुवर्षीय घास है। गर्म नमी वाला मौसम इसकी बढ़ोतरी के लिए उत्तम है। इसे 1500 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। यह बौनी किस्म है जो सम ऊष्ण कटिबंधी चारागाहों के लिए उपयुक्त है। यह सूखे को सहन कर सकती है तथा इसका तना व पत्ते नरम ही रहते हैं। ऊंचाई डेढ़ से दो मीटर तक ही रहती है। शुरू में प्रोटीन की मात्रा 9-10 प्रतिशत तथा बाद में 7-8 प्रतिशत रहती है। शुरू में आक्सालेट की मात्रा 2-3 प्रतिशत होती है बाद में कम होती जाती है।

भूमि व बिजाई-यह घास हाईब्रिड किसी भी प्रकार की भूमि पर उगाया जा सकता है। वैसे अच्छे किस्म वाली दोमट उपजाऊ भूमि इसके लिए उपयुक्त है। खुले खेतों में घासनियों में या दो खेतों के बीच की मेढ़ों या बीड़ों पर इसको लगाया जा सकता है। बरसात के मौसम के दौरान सितम्बर या अक्तूबर के पहले सप्ताह तक इसकी बीजाई चली रहती है।

यह जड़ों या तने की कलमों द्वारा तैयार होती है। एक जड़ या तने की कलम जिसमें कम से कम तीन आंखें हों, लगभग 22-27 हजार कलमें प्रति हेक्टेयर लगानी पड़ती है। मेढ़ों पर भी 60-70 सेंटीमीटर के अंतर पर छोटा सा गड्ढा (3-4 ईंच गहरा) करके इन कलमों को लगाया जा सकता है। 2-3 कलमें एक साथ लगानी चाहिए।

तीन चार वर्ष का पुराना पौधा उखाड़ देना चाहिए तथा नई कलमें लगा देनी चाहिए।

खाद व उर्वरक-नाइट्रोजन तथा फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीजाई के समय डालें तथा प्रत्येक कटाई के बाद 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हैक्टेयर डालें।

सिंचाई व गुड़ाई-यदि सिंचाई की सुविधा हो तो 15 दिन के अंतर पर और बरसात में वर्षा के अनुसार सिंचाई करें। प्रत्येक कटाई के बाद तथा नाइट्रोजन डालने से पहले गुड़ाई करें ताकि खरपतवार निकल जायें और भूमि नरम रहे।

कटाई-बीजाई के 40-45 दिन के बाद पहली कटाई मिल जाती है तथा इसके बाद सिंचाई वाले क्षेत्रों में हर 40-45 दिन के बाद कटाई मिलती रहती है। वर्ष भर 9-10 कटाईयां मिल जाती हैं। जहां सिंचाई की सुविधा न हो तो वहां पर 5-6 बार इसको काटा जा सकता है। सिंचाई वाले क्षेत्रों में यह घास वर्ष भर हरा चारा उपलब्ध करवाती रहती है। परन्तु असिंचित क्षेत्रों में चार महीनों (मई-जून व दिसम्बर-जनवरी) में हरे चारे की समस्या बनी रहत है।

इस घास हाइब्रिड में 7-8 प्रतिशत प्रोटीन होती है जोकि दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है। इस चारे को खिलाती बार एक सावधानी रखनी है कि खनिज मिश्रण दुधारू पशुओं को जरूरी खिलाना है ताकि पशुओं को दूध ज्वर न हो। अधिक दूध देने वाले पशुओं का कई बार दूध कम हो जाता है। यदि चारे के कुतरे को गेहूं भूसे में मिलाकर दें तो यह और भी उपयोगी बन जाता है। अधिक मात्रा में उपलब्ध होने पर इस हाईब्रिड का आचार भी बनाया जा सकता है।

–डॉ. संजीव उपाध्याय

बेमौसमी सब्जी उत्पादन में चम्बा बना सिरमौर

कोई बहुत पुरानी बात नहीं है जब सलूणी के किसान नकदी फसलों की खेती को ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। पर ग्रीन गोल्ड परियोजना ने न केवल उनकी सोच में बदलाव लाया बल्कि ग्रामीण आर्थिकी को भी नई दिशा दी। आज सलूणी ब्लॉक सब्जी उत्पादन में चम्बा जिले का सिरमौर बन चुका है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पोषित 14.88 करोड़ रुपये की ग्रीन गोल्ड परियोजन सलूणी के किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। परियोजना ने न केवल व्यावसायिक सोच पैदा करने में मदद की है बल्कि खेती के तरीकों को भी नई दशा व दिशा दी। आज सलूणी के जलाड़ी, जवांस, शालड्डू, अंकूजा, ग्रोहण, धनसू, प्रकेड व मेरू जैसे दर्जनों गांवों के खेतों में मटर, फ्रेंचबीन, फूलगोभी, बंदगोभी, आलू व टमाटर की लहलहाती फसलें खुशहाली की ओर बढ़ते कदमों की निशानदेही करती नजर आती हैं।

जिला ग्रामीण अभिकरण की देखरेख में संचालित इस परियोजना की बदौलत बेमौसमी सब्जियां उगाने वाले कई प्रगतिशील किसान एक मौसम में ही लाखों रुपये कमाकर अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर रहे हैं। खेती से मण्डी तक सब्जियां ढोने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ियां तक खरीद ली हैं।

ग्रीन गोल्ड परियोजना से जुड़ने के बाद सलूणी, हिमगिरि, डियूर, किहार व भंदल के करीब चार हजार किसानों ने अपनी तकदीर में खुशहाली के बीज बो दिये हैं। इनमें से तीन हजार किसानों ने बाकायदा स्वयं सहायता समूह भी बना रखे हैं। सरकारी पहल व वित्तीय मदद को अपनी आर्थिक समृद्धि का आधार बनाकर जिन किसानों ने वर्ष 2005 में 19 लाख रुपये की सब्जियां बेची वहीं आंकड़ा 10 लाख रुपये की बढ़ोतरी के साथ 29 लाख रुपये हो गया। अगले ही वर्ष सब्जियों के उत्पादन का नया रिकार्ड बना। किसानों ने 2007 में 62 लाख रुपये बटोरे। वर्ष 2008 में तो किसानों ने अपनी मेहनत के बूते सब्जियों के कारोबार को एक करोड़ के पार पहुंचा दिया।

सूरी पंचायत के प्रकेड गांव के प्रगतिशील किसान प्रहलाद के मुताबिक वह कभी पंजाब से सब्जियां लाकर बेचा करता था। लेकिन अब यहां पैदा होने वाली बेमौसमी सब्जियों ने उसकी जिंदगी ही बदल दी है। प्रहलाद के खेत आज सोना उगल रहे हैं। प्रहलाद के अलावा जलाड़ी गांव का मुश्ताक, ढल्ला गांव का जमीत सिंह, ग्रोहण गांव का महबूब, अंकूजा गांव का अब्बास व धनसू गांव का कंठ राम भी उन प्रगतिशील किसानों की फेहरिस्त में शामिल हैं जिन्होंने खेती को आर्थिक स्वावलम्बन से जोड़कर एक नई दिशा दे दी है।

किसानों द्वारा पैदा की जा रही सब्जियों के विपणन के लिए नरोई (सलूणी) में लघु सब्जी मण्डी खोली गई। मण्डी के संचालन के लिए गरिमो ग्रीन गोल्ड कृषक समिति का गठन किया गया है।

ग्रामीण आर्थिकी को खेती के जरिये महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंचाने वाले किसान वर्तमान जरूरतों के मद्देनजर कुछ और सुविधाओं की अपेक्षा कर रहे हैं। उन जरूरतों में किसान भवन और कोल्ड स्टोर प्रमुख हैं। यकीनन ग्रीन गोल्ड परियोजना से निकली खुशहाली की राह अभी और खुशरंग होगी।

–रवि वर्मा

देवतुल्य 'देवदार'

● विनोद भारद्वाज

भारतीय ग्रंथों अथर्ववेद से लेकर वाल्मीकि रामायण, महाभारत तथा भागवत तथा पुराणों में प्रकृति का वैज्ञानिक वर्णन मिलता है। वनस्पति को सर्वोच्च अधिमान एवं उपयोगिता प्रदान करने का श्रेय भारतीयों को ही है। इन सभी ग्रंथों में इसका सूक्ष्म व्याख्यान आज भी प्रासंगिक है।

भारतीयों ने प्रकृति की पूजा के विधान को अपनाया। हमारे लिए जल, जंगल, आकाश, पर्वत, वन, पशु-पक्षी सभी पूजनीय हैं। धरती की पूजा से ही सभी मांगलिक कार्य आरम्भ होते हैं। वनस्पति जगत की उपयोगिता को हमारे ऋषि-मुनियों ने करोड़ों वर्ष पूर्व ही जान लिया था। देवदार के सघन वन भारतीय ऋषियों की तपस्या के स्थल रहे हैं।

हिमालय की सुन्दरता जहां बर्फ से ढके पहाड़ों से है, वहीं यहां के हरे-भरे वन इसकी सुन्दरता को और अधिक बढ़ाते हैं। हिमालय की चोटियों पर देवदार की सुंदरता के बारे में महाकवि कालिदास ने, मनुष्य जीवन में पशुधन और वनस्पति धन की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। कालिदास ने देवदार को पार्वती के पुत्र की संज्ञा दी है।

कालिदास ने कुमारसंभव में देवदार वृक्ष की व्याख्या करते हुए वर्णन किया है-

भागीरथ निर्झर सीक राणां
वोदा मुहु: कम्पितदेवदारू:।
यद्वायुरन्विष्ट मृगै: किरातैर
आसिच्यते भिन्न शिखण्डि बर्हः।

गंगा जी के झरनों की फुहारों से लदा हुआ बारबार देवदारू के वृक्ष को कंपाने वाला और किरातों की कमर में लगे हुए मयूर के पंखों को फरफराने वाला यहां शीतल, मंद और सुगन्धित पवन उन किरातों की थकान मिटाना चाहता है, जो मृगों की खोज में हिमालय पर घूमते हैं।

सदाबहार देवदार पश्चिम हिमालय क्षेत्र का मूल वृक्ष है। यह पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान, उत्तर मध्य भारत (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, कश्मीर) तिब्बत के दक्षिण पश्चिम, पश्चिम नेपाल में 1500 से 3200 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यह वृक्ष 40-50 मीटर की ऊंचाई पाता है। यह वृक्ष का रूप ले लेता है तथा इसकी पत्तियां नुकीली होती हैं।

हिमालय क्षेत्र के अलावा यह पाइनस वृक्ष स्काटलैण्ड, रूस, फिलिपीन्स, नार्वे, साइबेरिया, अफ्रीका, कनाडा के उत्तरी भाग में बहुतायत में पाया जाता है। दुनिया भर में पाइन पेड़ की 125 से अधिक प्रजातियां मिलती हैं। इस वृक्ष की आयु 100 वर्ष से लेकर 1000 वर्ष तक होती है।

देवदार का अंग्रेजी विशेष नाम संस्कृत भाषा से 'देवदारू' लिया गया है जिसका अर्थ 'वुड ऑफ द गॉड' है। देवा (भगवान) तथा दारू (लकड़ी) है।

हिमाचल के वन हिमालय के मुकुट में हरे पन्ने के समान है। शिमला को मूलत: 'द हिल ऑफ देवदार' के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी के महान लेखक किपलिंग ने शिमला के देवदार का सुंदर व्याख्यान किया है। वर्ष 1885 में सर एडवर्ड बक ने शिमला नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी में शिमला की सुंदरता का बखान किया था। सिडर देवदार, लेबनान के सिडर से मिलती-जुलती प्रजाति है। माल रोड पर स्कैंडल प्वाइंट पर देवदार का वृक्ष 1881 में नगर निगम के गार्डन व आर्थर्ड इंचार्ज ए. पारसन ने लगाया था।

भारतीय उपमहाद्वीप में देवदार की सांस्कृतिक महत्ता

हिंदुओं में इसे ईश्वरीय वृक्ष माना जाता है। इसकी पूजा की जाती है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड में इसे पूजा जाता है तथा इसकी लकड़ी का उपयोग मंदिरों, देवालयों में किया जाता है। ऊर्दू में इसे देओदार, हिंदी-संस्कृत में देवदार, चीनी भाषा में ज्यू सोग (Xue Soug) कहा जाता है। अंग्रेजी राज के दौरान देवदार की लकड़ी का उपयोग पर्वतीय शहर बसाने, सैन्य छावनियां, सार्वजनिक भवन, पुलों तथा रेल लाइन के निर्माण में किया गया। पहाड़ों से लकड़ी की ढुलान नदियों से होकर मैदानों तक पहुंची।

आयुर्वेद में देवदार का उपयोग

भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में देवदार को औषधि के रूप में इस्तेमाल का उल्लेख मिलता है। देवदार की अंदरूनी लकड़ी खुशबूदार होती है तथा इसका उपयोगी इत्र बनाने में होता है। इस लकड़ी का विधायन कर इसका तेल निकाला जाता है। इसकी लकड़ी में मौजूद तेल के कारण कीड़ा नहीं लगता इसीलिए इसका तेल घोड़े, पशुओं तथा ऊंट के पैरों में लगाया जाता है।

पहाड़ों की तलहटी पर लगे वर्षभर हरे-भरे रहने वाले कोनिफर (शंकु वृक्ष) प्रजाति के वृक्ष धरा की सुंदरता को ही नहीं बढ़ाते, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इसकी प्रजातियां सबसे अधिक वाणिज्यिक महत्त्व की होती है। विश्वभर में इसकी लड़की का उपयोग अनेक प्रकार से किया जाता है। अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली प्रजाति (PINUS Gerardiana) के बीज (नियोजा) खाने के काम आते हैं। जबकि कम ऊंचाई पर पाई जाने वाली प्रजाति से निकलने वाले बिरोजा का उपयोग से अनेक उत्पादों को बनाने में होती है। 19वीं शताब्दी में बिरोजे की उपयोगिता का पता चला। इससे रेजिन आयल तैयार कर इसका उपयोग रंग तथा औषधीय उपयोगों के लिए किया जाने लगा। स्वीडन में सर्द ऋतु में इसकी नुकीली पत्तियों से चाय बनाई जाती है। इसकी बाहरी परत विटामिन ए तथा सी से भरपूर होती है।

हिमाचल में 37,033 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। दो हजार मीटर से 3 हजार मीटर की ऊंचाई पर देवदार की प्रजातियां मिलती हैं। हिमाचल प्रदेश में कोनिफर की 13 प्रजातियां पाई जाती हैं- पाइनस वालिचयाना, पाइनस सोक्सवर्गी, पाइनस जरिडयाना, पाइनस समीययाना, ऐबिस पिनडरो, ऐबिस सपैक्टीयाबैलिस, क्यूपरिसर टोरोलोसा, सिडरस देवदार, जूनिपेरिस मैकरोपैन्डा, जूरिपेरिस एक्सीलेसा, ज्यूपेरिस स्कूपमैरा, एफिडेरा जैरिडियाना तथा टैक्सस बैकाराटा।

देवदार के तहत 811 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रदेश में है।

हिमाचल के वन हिमालय के मुकुट में हरे पन्ने के समान है। शिमला को मूलत: 'द हिल ऑफ देवदार' के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी के महान लेखक किपलिंग ने शिमला के देवदार का सुंदर व्याख्यान किया है। वर्ष 1885 में सर एडवर्ड बक ने शिमला नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी में शिमला की सुंदरता का बखान किया था। सिडर देवदार, लेबनान के सिडर से मिलती-जुलती प्रजाति है। माल रोड पर स्कैंडल प्वाइंट पर देवदार का वृक्ष 1881 में नगर निगम के गार्डन व आर्थर्ड इंचार्ज ए. पारसन ने लगाया था।

शिमला की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए हाल ही में देवदार पुनर्जीवीकरण पौधरोपण कार्यक्रम आरंभ किया गया। मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने आराम किया। इसके तहत तीन हजार पौधे रोपे जा रहे हैं। इस अभियान को आरम्भ करते हुए प्रो. धूमल ने कहा कि 'शिमला की पहचान देवदार है। अगर शिमला को बचाना है तो देवदार को रोपण होगा।'

हाल ही में शिमला को देश के सुंदरतम पर्यटक स्थल का पुरस्कार भी मिला है। देवदार शिमला की शान है।

इस कार्यक्रम में लगभग 11 स्वयंसेवी एवं गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया गया है। इस अभियान से शिमला जिसे पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है, के पुराने वैभव को बनाए रखने में सहायता मिलेगी। सरकार का यह प्रयास प्राचीन भारतीय परम्परा का हिस्सा है तथा देवतुल्य देवदार के वृक्षों से शिमला की पहाड़ियों को सदैव हरा-भरा रखने का भगीरथी प्रयास है।

शाह मस्त अली मजार

आपसी सद्भावना की प्रतीक

● जोगिन्द्र राणा

हिमाचल की सुरम्य वादियों में महान ऋषियों-मुनियों ने तप किया व अनेक ग्रंथों की रचना की है। यहां के गांव-गांव में इन विभूतियों से जुड़ी मान्यताएं एवं परम्पराएं हैं जिन्हें आज भी स्थानीय लोगों ने जिंदा रखा है। समृद्ध धार्मिक संस्कृति के प्रतीक असंख्य मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे यहां की अमूल्य धरोहर हैं। कांगड़ा जिले के उपमण्डल जयसिंहपुर के जयसिंहपुर-हारसीपत्तन मार्ग पर स्थित बाबा शाह मस्त अली की तीन सौ वर्ष पुरानी मजार, साम्प्रदायिक सद्भाव की प्रतीक है। लगभग दो हजार की आबादी वाले जयसिंहपुर कस्बे में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता है। लेकिन पीर बाबा शाह मस्त अली की मजार की देखरेख व प्रतिदिन पूजा-अर्चना स्थानीय हिन्दू परिवार ही करते हैं। स्थानीय वासियों ने मजार के सौंदर्यकरण के लिए एक कमेटी गठित की हुई हैं जिसके प्रयासों से इस धार्मिक धरोहर का संरक्षण सुनिश्चित हुआ है। यहां वैदिक हिन्दू लोगों द्वारा मजार पर धूप, दिये, जल एवं नैवेद्य चढ़ाया जाता है। मजार के समीप ही नीलकण्ठ महादेव का मंदिर है।

मान्यता के अनुसार बाबा शाह मस्त लगभग तीन सौ वर्ष पूर्व जयसिंहपुर में निवास करते थे। उनकी प्रसिद्धि दूर-दूर तक थी। एक दिन वे भिक्षा मांगने, एक घर पर गये। मालकिन ने संतान न होने का दु:ख बाबा के समक्ष रखा। बाबा ने संतान होने का आशीर्वाद दिया और कहा कि 12 वर्ष की उम्र में वे उसे अपने साथ ले जाएंगे। बाबा को यह बालक भिक्षा में मिला था इसलिए इसका नाम भीखू पड़ा। बाबा ने उसे सभी विधाओं में पारंगत किया। वह बाबा के लिए जंगल से लकड़ियां लेकर प्रतिदिन आता था। एक दिन भीखू को जंगल में अनेक लोग एक अर्थी को ले जाते दिखे। उसने पूछा आप इतनी सारी लकड़ियां कहां लेकर जा रहे हैं। लोगों ने कहा कि इसके अंतिम संस्कार के लिए। भीखू ने कहा अगर मैं इसको जिंदा कर दूं तो क्या आप सभी लकड़ियां मुझे दे दोगे। भीखू ने उस मृत व्यक्ति को जिंदा कर दिया। भीखू की प्रसिद्धि सारे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई।

जब बाबा शाह मस्त अली को अपनी दिव्य दृष्टि से इस बात का पता चला तो वे बहुत ही गुस्सा हुए। प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाने के लिए बाबा ने भीखू को सजा देने की सोची। भीखू बाबा के हाथ नहीं आया तथा भवारना में उसने समाधि ले ली।

सौ वर्षों से यहां मन्नत मांगने वालों का तांता लगा रहता है। लोग मजार पर चने का प्रसाद वीरवार को चढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त पीला प्रसाद लड्डू व बूंदी भी चढ़ाई जाती है। जिस किसी को चर्म रोग (मुहासे) होते हैं तो वह ठीक करने के लिए मन्नत मांगता है। रोग ठीक होने पर नमक चढ़ाया जाता है। 29 मई को प्रतिवर्ष यहां भण्डारे का आयोजन होता है, जिसकी देखरेख स्थानीय हिन्दू परिवार ही करते हैं।

बाबा शाह अली की मजार पर स्थानीय व आसपास के क्षेत्रों के लोग तो आते ही हैं लेकिन पंजाब के होशियारपुर व अन्य जिलों के लाखों लोग भी यहां आकर अपना शीश नवाते हैं। बाबा शाह मस्त अली की शिक्षा व दर्शन व वाणी आज अनेक मतों में भी मिलती है।

भीखा भूखा को नहीं
सबकी गठरी लाल
गिरह खोलन जानसी।
ता-ते भय कंगाल।

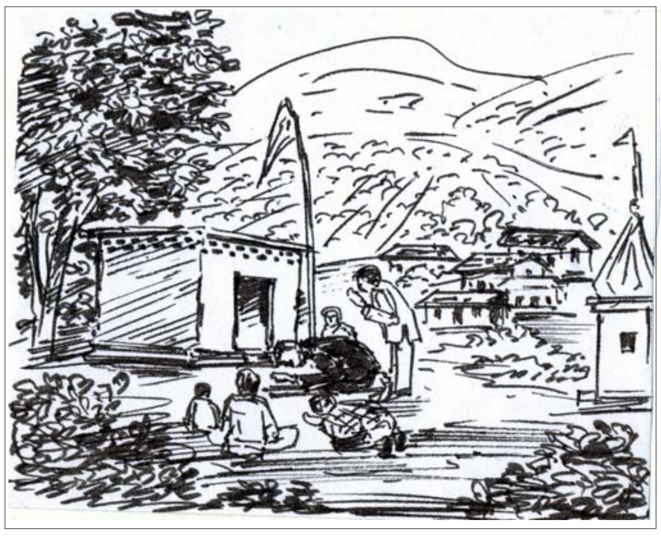

नरेश माता मंदिर

बिलासपुर में अनेक ऐतिहासिक मंदिर हैं। ये मंदिर स्थानीय लोगों व उत्तरी भारत की अधिकांश आबादी में आस्था के केन्द्र हैं। इन्हीं मंदिरों में एक है नरेश माता मंदिर जो भगेड़-समोह- गेहड़वीं मार्ग पर भगेड़ से 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मंदिर की देखभाल एक स्थानीय प्रबंधक कमेटी करती है। यह मंदिर गांव नरेश में पड़ता है। स्थानीय पंडित बृजलाल के अनुसार अतीत में यहां घना जंगल था तथा सदियों पूर्व यहां संत तप में लीन रहते थे। बाबा वनखंडी नामक सिद्ध पुरुष भी यहां रहते थे। मां नरेश मंदिर के तल भाग में बाछड़ जंगल की ऊपरी पट्टी में कुछ गुफाएं हैं। इनमें से एक गुफा गोरखनाथ की है। परमसिद्ध लक्ष्मण गिरि जी की चरणपादुकाएं तथा पाषाण चौकी लघु गुफा में हैं। जनश्रुति है कि चक्रवर्ती सम्राट सरुथ ने भी यहां तप किया था। उसी राजा के नाम पर इस स्थान का नाम संभवत: नरेश हुआ। मंदिर में पूजी जाने वाली पिंडी सदियों पुरानी है तथा मूर्ति प्राचीन है। कालांतर में राजा कल्याण चंद ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था।

● घनश्याम गुप्ता

प्रकृति की अनुपम कृति चन्द्रताल

● रोशन लाल ठाकुर

हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति में समुद्रतल से 4420 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चन्द्रताल, प्रदेश के शीत मरुस्थल के प्राकृतिक जलाशयों में से एक है। ऐसा मत है कि जलाशय का स्वरूप अर्धचन्द्राकार होने के कारण इसका नाम चन्द्रताल पड़ा।

चन्द्रताल के जल के उद्गम क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन जल एक छोटी नदी द्वारा चन्द्रा नदी में अवश्य मिलता है। यह झील चन्द्राघाटी के ऊपर कुंजम शृंखलाओं के मध्य में स्थित है जो कि वृहद हिमालय तथा पीर पंजाल शृंखला के बीच में पड़ती है। चन्द्रताल से समुद्रा तायो ग्लेशियर तथा मलिका पर्वतमाला के दर्शन होते हैं। यहां पहुंचने के लिए मनाली से काजा मार्ग पर 120 किलोमीटर दूरी तय कर बातल नामक स्थान पर पहुंचा जा सकता है तथा वहां से चन्द्रताल तक की दूरी 14.5 किलोमीटर छोटे वाहन व पैदल चलकर तय की जा सकती है। यहां से कुंजम दर्रा 12 किलोमीटर तथा बारालाचा दर्रा 40 किलोमीटर दूर है।

वर्ष 1909 से पूर्व चन्द्रताल जलाशय तक पहुंचने के लिए कोई ज्ञात मार्ग नहीं था। सर्वप्रथम कांगड़ा तथा चम्बा के भेड़ पालकों ने इस स्थान को खोजा। वर्ष 1909 में सबसे पहले चन्द्रताल जलाशय को पालमपुर के गांव आसानपट्ट के निवासी वक्तोर राम ने देखा था। वह वहां भेड़-बकरियों के साथ दो माह तक रुका था। उसने इस मनोरम स्थान की जानकारी अन्य भेड़ पालकों दासा राम व धर्म चन्द (गोपालपुर), प्रह्लाद (कंडी) को दी। वक्तोर राम ने इस स्थान की जानकारी ब्रिटिश अधिकारियों को भी दी।

वर्ष 1911 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने चन्द्रताल जलाशय के इर्दगिर्द की चरागाहों को वक्तोर के नाम करवा दिया। जब चन्द्रताल पर्यटन स्थल को सड़क मार्ग से जोड़ा गया तो तत्कालीन प्रदेश सरकार ने उसे 10 हजार रुपये का मुआवजा दिया था।

वर्ष 1909 से पूर्व चन्द्रताल जलाशय तक पहुंचने के लिए कोई ज्ञात मार्ग नहीं था। सर्वप्रथम कांगड़ा तथा चम्बा के भेड़ पालकों ने इस स्थान को खोजा। वर्ष 1909 में सबसे पहले चन्द्रताल जलाशय को पालमपुर के गांव आसानपट्ट के निवासी वक्तोर राम ने देखा था। वह वहां भेड़-बकरियों के साथ दो माह तक रुका था।

जिला कुल्लू के गिरु (लग घाटी) के भेड़ पालक कांगड़ा तथा चम्बा के गद्दियों के साथ गर्मियों में यहां जाते थे। भेड़ पालक बारालाचा, सरचू, लिंगटी तक जाते हैं। भेड़ पालक प्रस्थान के समय वर्सेऊ जोत (दर्रा) के समीप मेला आयोजित करते हैं। इस दौरान सभी मिलकर लोकगीत गाते हैं। वाद्य यंत्रों में लोहे का लोहिया (दूध रखने का छोटा कटोरा) बजाया जाता है। हिन्दू मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर को भगवान इंद्र का रथ यहां से मानव शरीर में ही स्वर्ग ले गये थे।

सुंदर एवं मनोरम चन्द्रताल झील के किनारे विदेशी सैलानी

चन्द्रताल जलाशय का कुल क्षेत्रफल 1.53 वर्ग किलोमीटर तथा परिधि 2.5 किलोमीटर है। वर्ष के अधिकांश समय यहां बर्फ रहती है तथा शीत ऋतु में तापमान शून्य से 40 डिग्री नीचे चला जाता है तथा झील पूर्ण रूप से जम जाती है।

चन्द्रताल के जल ग्रहण क्षेत्र में मुख्यत: अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है, जिनमें पौआ व एग्रोपाईरैन घास तथा पोटेनटाईला, रेनुनकलस, रोजुलेरिया, एक्वीलीजिया व प्रिमुला आदि प्रमुख हैं। इस क्षेत्र में वन्य प्राणियों में हिमालयन मार्मोट, मोलरैट, टंगरोल, भेड़िया, बर्फानी तेंदुआ, हिमालयन फोक्स व बर्फानी मुर्गा देखे जा सकते हैं।

चन्द्रताल का शीतल व शुद्ध जल तथा शांत वातावरण गर्मियों में हजारों प्रवासी पक्षियों की शरण स्थली बनती है तथा वे यहां प्रजनन के लिए आते हैं। इनमें ब्लैक विंगड स्टिलर, ब्राह्मणी डक, तथा गोल्डन ईगल इत्यादि प्रमुख हैं।

यहां प्रतिवर्ष जून माह से अगस्त तक हजारों देशी व विदेशी पर्यटक आते हैं। मनाली-काजा मार्ग पर जलाशय से लगभग 30 किलोमीटर पूर्व छोटा-दड़ा नामक स्थान पर लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह है। जबकि लोसर में भी विश्राम गृह की सुविधा मौजूद है। यहां अनेक पर्यटक तम्बू लगाकर रहते हैं।

सरकार द्वारा प्राकृतिक सौंदर्य को संरक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए एक योजना तैयार की गई है जिसके तहत भू-संरक्षण, जड़ी-बूटियों का संरक्षण तथा जलाशय के आसपास के क्षेत्र को यथावत बनाए रखना है। बातल क्षेत्र में इस कार्य योजना को मूर्त रूप देने के लिए सूचना केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

समृद्ध संस्कृति की झलक

आस्था/मेले

● बी.आर. चौहान

देवभूमि हिमाचल में असंख्य ऐतिहासिक एवं प्राचीन मन्दिर विद्यमान हैं, जिनके नाम पर हर वर्ष सम्बन्धित क्षेत्र के लोग खुशहाली और समृद्धि के लिये मेलों का आयोजन करते हैं, कांगड़ा जिला के तीन शक्तिपीठ नवरात्र मेलों के अतिरिक्त वर्षभर श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त शिव मन्दिर बैजनाथ में श्रावण मास तथा महाकालेश्वर महादेव मन्दिर महाकाल में भादप्रद मास में भोले शंकर की कृपा एवं प्रसन्नता हेतु एक मास तक विशेष मेलों का आयोजन होता है। परन्तु प्रदेश और जिला कांगड़ा में दो मास तक चलने वाला केवल मात्र एक नागनी माता का मेला है, जो हर वर्ष श्रावण मास के प्रथम शनिवार से प्रारम्भ होकर भादप्रद मास के अन्तिम शनिवार तक चलता है।

नागनी माता का प्राचीन एवं ऐतिहासिक मन्दिर नूरपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर मण्डी- पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर गांव बड़वार के समीप कोहड़ी टीका गांव में स्थित है। नागनी माता जोकि मनसा माता का रूप माना जाता है, के नाम पर हर वर्ष श्रावण एवं भादप्रद मास में आयोजित होने वाले नौ मेलों की शृंखला में इस साल मेला 18 जुलाई से आरंभ होकर 12 सितम्बर को समाप्त हुआ। इन्हीं में से एक मेला ज़िला स्तरीय घोषित किया गया है, जोकि पहली अगस्त को मन्दिर परिसर में परम्परागत एवं बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

इस मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन है और इसकी विशेषता यह है कि इसके पुजारी राजपूत घराने से संबन्धित हैं। इस मंदिर को लेकर कई दंत कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं की सच्चाई जो भी हो, परंतु लोग श्रद्धाभाव से जहरीले जीवों, कीटों तथा सर्पदंश के इलाज के लिए यहां आते हैं।

नागनी माता मंदिर की स्थापना को लेकर प्रचलित एक कथा में इस जगह का नाम टीका कोढ़ी बताया जाता है, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। कोढ़ से ग्रसित एक वृद्ध इस जंगल में रहता था और रोग से मुक्ति के लिए भगवान से निरंतर प्रार्थना करता रहता था। उसकी साधना सफल होने पर उसे नागनी माता के दर्शन हुए तथा नाले में दूध की धारा बहती दिखाई दी। स्वप्न टूटने पर उसने दूध की धारा वास्तविक रूप में बहती देखी। माता के निर्देशानुसार उसने अपने शरीर पर उसका लेप किया और वह कोढ़मुक्त हो गया। आज भी यह परिवार माता की सेवा करता है और माना जाता है कि उसके परिवार को माता की दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं।

नागनी माता मंदिर

मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन है और इसकी विशेषता यह है कि इसके पुजारी राजपूत घराने से संबन्धित हैं। इस मंदिर को लेकर कई दंत कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं की सच्चाई जो भी हो, परंतु लोग श्रद्धाभाव से जहरीले जीवों, कीटों तथा सर्पदंश के इलाज के लिए यहां आते हैं।

इसी तरह एक अन्य कथा के अनुसार एक नामी सपेरे ने मंदिर में आकर धोखे से नागनी माता को अपने पिटारे में डालकर बंदी बना लिया। नागनी माता ने क्षेत्रीय राजा को दर्शन देकर अपनी मुक्ति के लिए कहा। जब वह सपेरा कंडवाल के पास आकर रूका तो, राजा ने नागनी माता को उससे मुक्त करवाया। तब से इस स्थल को विषमुक्त होने की मान्यता मिली और सर्पदंश से पीड़ित लोग अपने इलाज के लिए यहां आने लगे। इसी तरह कुछ अन्य कथाएं भी इस मंदिर की मान्यता को लेकर प्रचलित हैं। मन्दिर के पुजारी प्रेम सिंह के अनुसार माता कई बार सुनहरी रंग के सर्परूप में मन्दिर परिसर में दर्शन देती है, जिसे देखकर बड़े आनन्द की अनुभूति होती है और वह क्षण हृदय में चिरस्मरणीय रहते हैं।

यूं तो इस मंदिर में वर्ष भर श्रद्धालु अपनी आस्था प्रकट करने के लिए आते रहते हैं। परंतु, श्रावण-भाद्रपद के दौरान आयोजित होने वाले नौ मेलों में हिमाचल के अलावा पंजाब, हरयिाणा, दिल्ली, प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू- कश्मीर के श्रद्धालु नागिनी माता के दर्शनों के लिए विशेषरूप से पहुंचते हैं।

जिला स्तरीय मेला घोषित होने पर उपमण्डलाधिकारी(ना) नूरपुर की अध्यक्षता में मन्दिर प्रबन्धन समिति का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से मन्दिर के विशाल भवन के निर्माण के अतिरिक्त श्रद्धालुओं एवं सांप से पीड़ित व्यक्तियों के ठहरने हेतु तीन धर्मशालाएं, एक यज्ञशाला, एक भण्डार कक्ष तथा एक सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया गया है। महिलाओं के लिये अलग से स्नानागार निर्मित किया गया है। राजमार्ग से मन्दिर परिसर तक सड़क एवं रोशनी का प्रबन्ध किया गया है तथा वाहनों के लिये पार्किंग स्थल बनाये गये हैं।

श्रद्धालु माता के मन्दिर की मिट्टी जिसे शक्कर कहा जाता है, को बड़ी श्रद्धा व विश्वास के साथ घर ले जाते हैं ताकि घर में सांप तथा अन्य विषैले जन्तुओं का भय न रहे। मेले के दौरान लोग द्वारा नागनी माता को दूध, खीर, फल इत्यादि अर्पण करके पूजा आराधना की जाती है। आदिकाल से यह मेला बदलते परिवेश के बावजूद भी लोगों की श्रद्धा एवं आस्था का परिचायक रहा है, जिसमें प्रदेश की समृद्ध संस्कृति एवं सभ्यता की झलक साक्षात देखने को मिलती है।

शिक्षक दिवस पर विशेष

मानव मूल्य, शिक्षा और डॉ. राधाकृष्णन्

'दर्शन शास्त्र की आवश्यकता तभी पड़ती है जब परम्पराओं की नींव हिल जाती है।'
-डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्

आज जब हम कल्चर अर्थात संस्कृति, सभ्यता, मूल्य परम्परा आदि की बात करते हैं तो जाने-अनजाने हमारा दायरा सीमित हो जाता है चाहे हम ग्लोबलाइजेशन के युग में रह रहे हैं। यह आश्चर्य की बात है क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब भूमण्डलीकरण शब्द था ही नहीं किन्तु मनुष्य की सोच 'वसुधेव: कुटुंबकम्' तक विस्तृत थी और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देती थी। ऐसे ही द्रष्टा थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण।

डॉ. राधाकृष्णन् भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, एक जाने-माने राजनीतिज्ञ थे, स्वतन्त्रता सेनानी थे, ख्यातनाम दार्शनिक भी थे किन्तु मूलत: वह अपने आपको एक शिक्षक ही मानते थे और यही कारण है कि उनका जन्म दिन पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका मानना था कि शिक्षा ही एक ऐसा शस्त्र है जो समाज में चेतना ला सकता है। वह ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिसकी नींव भारतीय संस्कृति हो, पर जिसमें आधुनिक वैज्ञानिक विचारों को आत्मसात करने की दक्षता हो। यह समाज तभी बन सकता है जब शिक्षा प्रणाली में बच्चों का आत्म विकास, सर्वांगीण विकास तथा आधुनिक तकनीकी विकास आदि का भरपूर प्रयोजन हो।

शिक्षा में हमारे अपने सांस्कृतिक मूल्य ही नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों का समावेश भी होना आवश्यक है। मूल्यों को हम पांच भागों में बांट सकते हैं, जैसे निजी मूल्य, पारिवारिक मूल्य, सामाजिक मूल्य देश के अर्थात सांस्कृतिक मूल्य तथा मानव मूल्य। पहले चार मूल्य समय के साथ बदल सकते हैं किन्त मानव मूल्य शाश्वत हैं। यह देश, काल, संस्कृति आदि सबसे ऊपर हैं और ये हैं-सत्य, धर्म, शांति और प्रेम। ये चार स्तम्भ हैं जिन पर शताब्दियों से मानव सभ्यता टिकी है। चरित्र निर्माण में चारों का बड़ा महत्व है। तभी डॉ. राधाकृष्णन् कहते हैं, 'अपने देश को हम ईंट, पत्थर, सीमेंट से नहीं बना सकते। सांस्कृतिक मूल्य हमारे युवाओं के दिलो-दिमाग में पैठ कर पनपने चाहिए।'

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् जब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (उच्च शिक्षा आयोग) के अध्यक्ष थे तब उन्होंने ऐसी उच्च शिक्षा नीति बनाने का प्रयत्न किया जिसमें भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य तकनीकी प्रगति का मिला जुला प्रावधान हो। जैसा कि अमेरिकन कवि ई. डब्ल्यू. इमरसन अपनी एक कविता में कहते हैं कि कोई भी देश सोने-चांदी व भौतिक प्रचूरता से बड़ा नहीं बनता बल्कि अपने नागरिकों के चरित्र से बनता है, ऐसे लोगों से जो अथक प्रयत्न करते नहीं थकते। डॉ. राधाकृष्णन् चरित्र निर्माण पर बल देते थे और कहते थे कि किसी भी राष्ट्र का चरित्र उसके नागरिकों में आंका जा सकता है। वही राष्ट्र बड़ा और प्रगतिशील होता है जिसके युवा स्वयं उच्च विचारों वाले हों। इसीलिए हमें अपने युवकों और युवतियों को ऐसी शिक्षा देनी है जो उन्हें दृढ़ चरित्र की ओर प्रेरित करे।

शिक्षा ऐसी हो जो विद्यार्थी की भावनाओं, विचारों, व्यवहार को प्रशिक्षित करे ताकि बच्चे विचार और व्यवहार में प्रगल्भ हों। अब प्रश्न उठता है कि मानवीय मूल्यों की बात तो हम करते हैं परन्तु इन्हें जीवन में कैसे ढाला जाये। इसके लिए डॉ. राधाकृष्णन् स्कूली पुस्तकों और शिक्षक की भूमिका को अहम स्थान देते हैं। अच्छे स्तर का पाठ्यक्रम बच्चों में मूल्यों का धीरे-धीरे विकास करने में सक्षम होता है। साथ ही अच्छे चरित्र के आदर्श शिक्षक ही मूल्यों को बच्चों में कूट-कूटकर भर सकते हैं। मूल्य केवल सतही न हों, बल्कि ऐसे हों जो हर

● डॉ. उषा बंदे

परिस्थिति में अडिग रहें, जो देश की अनेकता को समझें और उस अनेकता में एकता देखें। इसके लिए उनके विचार से शिक्षक पूरी तरह से उत्तरदायी हैं। शिक्षक स्वयं उच्च स्थान व आदर तभी पाता है जब वह समर्पित हो। 'युवा भारत को गढ़ने में शिक्षक का एक खास स्थान है।' अपने कई भाषणों में उन्होंने कहा है। आध्यात्म, शिक्षा, चरित्र, युवाओं का मूल्यों को संजोने में योगदान आदि विषयों पर डॉ. राधाकृष्णन् के विचार स्वामी विवेकानन्द से प्रेरित थे ऐसा उन्होंने कई बार कहा है।

डॉ. राधाकृष्णन् का जन्म चैन्नई से 64 किलोमीटर दूर स्थित तिरुतानी नामक स्थान पर 5 सितम्बर, 1888 को हुआ किन्तु अत्यंत मेधावी होने के कारण उन्हें अलग-अलग विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के रूप में बुलावा आता रहा। दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से कार्य आरम्भ किया, तत्पश्चात् कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्हें नियुक्त किया गया। ऑक्सफोर्ड में भी उन्होंने पढ़ाया। आंध्र विश्वविद्यालय तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वह उपकुलपति रहे। यही कारण है कि उन्होंने अपने को एक शिक्षक के रूप में ही देखा हालांकि वे भारत के उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति भी रहे, पर अन्तर्मन से वह शिक्षक रहे और शिक्षा के प्रति समर्पित रहे। बच्चों में अर्थात् विद्यार्थियों में भौतिकता के साथ- साथ आध्यात्मिक शक्ति हो यही उनका मानना था। आध्यात्मिक शक्ति ही मनुष्य को मानवीय मूल्यों के प्रति सजग व सचेत करती है जो युग की मांग है।

आज जीवन मूल्यों का इतना विघटन हो गया है कि मानवीय मूल्यों के लिए कहीं स्थान ही नहीं बचा है। शिक्षा संस्थानों में रैगिंग, बुल्लिंग, अनुशासनहीनता आदि तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में एक बारगी डॉ. राधाकृष्णन् जैसे शिक्षाविदों को याद करना महज एक औपचारिकता न रहकर वास्तविकता हो जाये तो डॉ. राधाकृष्णन् को हम सही मायनों में श्रद्धा सुमन देंगे। 1946 में इस विद्वान ने एक भाषण में कहा था कि दुनिया के देश भौगोलिक तौर पर अवश्य निकट आ गये हैं परन्तु मानसिक तौर पर नहीं। मानसिक एकता तभी आएगी जब लोग मानवीय मूल्यों को समझेंगे और उनको व्यक्तिगत का भाग बनायेंगे। शिक्षक दिवस तभी सही मायनों में सार्थक होगा।

कविता

भारत गौरव

मंदिरों में गूंजती घंटियों की
मधुर पवित्र ध्वनि सुनाई देती थी
सुबह शाम जहां,
शंख ध्वनि उद्घोषित कराती थी
जीवन का उल्लास जहां,
यज्ञशालाओं से उठते
धूम से पावन होती
सुबह शाम जहां
दिशाओं में गूंजता
वैदिक ऋचाओं का था
गान जहां,
प्रात: चहचहाती चीड़िया
सुनाती थी जीवन का
मधुर राग जहां,
प्रात: उगते सूरज की
किरणें प्रतिदिन लाती
नवजीवन का संदेश जहां,
उगते चांद की
कोमल रश्मियां
करती मधुवर्षा जहां,
पनघट खलिहान में
जीवन संचार करती
वनिताओं की
पदचाप जहां
ग्रामीण बालाओं की
निश्छल मुस्कान
हरती जीवन की
थकान जहां,
आज...
कलंकित कलुषित
हुआ भ्रूण हत्या
के दोष से
समाज वहां,
गर्भ में ही बेटियों की
की जा रही हत्या वहां
आसमान में व्याप्त है
उनका करूण कन्दन वहां
मां बाप के ही हाथों
छिनता
आज जीवन यहां
इस भयानक आर्तनाद से
कांपती है रूह यहां
क्या यही गौरव
रह गया है आज
भारत मां का यहां।

▸▸डॉ. किशोरी लाल शर्मा

क्या आप जानते हैं?

मकड़ी अपने जाल में खुद क्यों नहीं फंसती

मकड़ी अपने शरीर से जो रेशमी जाल तैयार करती है उसके सभी तार चिपकने वाले नहीं होते। वह दो प्रकार के तार तैयार करती है। खुद चलने के लिए वह बिना चिपकने वाले तार इस्तेमाल करती है। इसके अलावा मकड़ी के शरीर की एक ग्रन्थि ऐसा तरल तैयार करती हैं जो उसके पैरों पर लगा होता है। इस कारण भी उसके पैर जाल से नहीं चिपकते हैं। मकड़ी के पैरों की बनावट भी खास तरह की होती है। पेड़ की शाखा पर चलते वक्त उसके जो पंजे काम में आते हैं वे जाल में चलते वक्त अलग रहते हैं। उनकी जगह पैर में छिपे छोटे-छोटे हुक जाल में पैर रोकने का काम करते हैं।

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का मुख्यालय कहां पर है?
2. विश्व में काफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है?
3. विश्व रिकॉर्ड की पहली गिनिज पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी?
4. साहित्य के लिए वर्ष 2007 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था?
5. भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है?
6. किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं?
7. भारतीय न्यूक्लीय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है?
8. टेमिफ्लू किसके लिए एक प्रमुख औषधी है?
9. संविधान में किस संशोधन से 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई हैं?
10. तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है?
11. नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' किस जेल में लिखी गई थी?
12. देश का पहला 'आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण' संस्थान कहां स्थापित किया जा रहा है?
13. 'देवधाम हिमाचल' पुस्तक के लेखक कौन हैं?
14. पशुपति नाथ शिव का मंदिर कहां स्थित है?
15. निरशू मेले का आयोजन हिमाचल में कहां होता है?
16. 'छोदपा' से क्या अभिप्राय है?
17. ऐंकली किसे कहा जाता है?

प्रस्तुति-जया चौहान

❑❑❑

उत्तर-1. जेनेवा (स्विटजरलैंड में), 2. ब्राजील, 3. 1954 में, 4. डोरिस लैसिंग को, 5. तारापुर, 6. कावेरी, 7. होमी जे. भाभा, 8. स्वाईन फ्लू, 9. 92वें, 10. 159 लीटर, 11. अहमद नगर फोर्ट, 12. लातूर महाराष्ट्र में, 13. शांति कुमार स्याल, 14. अर्कीनगर से सटे गाहर में, 15. जिला कुल्लू के निरमंड गांव में, 16. जिला किन्नौर में भोजन परोसने के बाद तथा खाना शुरू होने से पहले पढ़ा जाने वाला मंत्र, 17. दीवाली के अवसर पर बनने वाला बिलासपुर जिले का विशेष पकवान।

व्यंग्य

कुत्ता संस्कृति के क्या कहने

कोई भी रास्ता निरापद नहीं है। रास्तों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हैं या फिर कुत्ते। चौड़ी सड़कें दुर्घटनाओं से छोटी होती जा रही है या छोटी सड़कें चौड़ी होकर जानवरों की विचरणस्थली बन गई हैं। उधर आदमियों के कद घटते जा रहे हैं और इधर जानवरों में कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है।

लोग अपने बड़े बुजुर्गों को बर्दाश्त नहीं करते हुए उन्हें घरों से निकाल रहे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए कुत्तों को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह कुत्ता संस्कृति का विकास ही है कि लोगों को आदमी जीवधारी से सख्त नफरत है और कुत्तों से बेहद प्रेम। कुत्ते भी अपना स्थायी घर चाहते हैं। उन्हें सिविल लाइन्स, सी-स्कीम, बापू नगर, गांधी नगर और जवाहर नगर जैसी बड़ी बस्तियों में बसने से चिढ़ है और वे छोटी बस्तियों में अपने को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। छोटी बस्तियों में वे यहां-वहां और सब कहीं दौड़ते हैं, जैसे तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र या लाभ उन्हें ही मिला हो या जनसत्ता में उनकी भी कोई भागीदारी हो।

छोटी बस्तियों की कुत्ता संस्कृति नये-नये रूपों में सामने आने लगी हैं कुत्ते खोल दिये जाने पर तो आसपास तोड़-फोड़ करते हैं या आगुन्तकों को काटते हैं। यह बात चारों ने अच्छी तरह समझ ली है कि कुत्ते रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं। अब चोरियां भी दिनदिहाड़े होने लगी हैं और रात में चोर नहीं आते। चोरों के मुकाबले के लिए आदमियों की तरह अब कुत्ते भी स्वस्थ मस्त होना चाहते हैं। रांची में योग के बढ़ते क्रेज से कुत्ते भी अछूते नहीं रह गये हैं। झारखण्ड में एक कुत्ता इन दिनों चर्चा में है कि यह योग के कई आसनों और मुद्राओं को आजमाने की काबलियत रखता है। यह कुत्ता अपने प्रशिक्षक के निर्देशन में योग करता है।

कुत्ते स्वामी भक्त जरूर हैं, पालतू और पहचानदार भी, किन्तु उनका मिजाज कब बिगड़ जाये, यह बात कोई नहीं जानता। हर व्यक्ति चाहता है उसका कुत्ता उसका बनकर रहे या वह कुत्ते के साथ रहे अथवा कुत्ता जैसा रहे, किन्तु दूसरे कुत्तों की हरकत को देखकर घर का कुत्ता भी पराया होने लगता है।

हमारी बस्ती के निवासी देवतुल्य हैं और कुत्तों के प्रेमी भी। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए कुत्ते रखकर दूसरों का जीवन हराम कर रखा है। कुत्तों की पहचान भी उनके मालिकों के नाम से है यथा, प्रयागचन्द्र जी का कुत्ता, रमण जी की कुतिया, हरिचरण का कानिया कुत्ता, प्रभुजी की चितकबरी कुतिया, लालजी का पिल्ला, व्यास जी की पीली पिल्ली, लोकरथ जी का सफेद डॉग और मिर्जाजी की डॉगी।

पहले घरों के बाहर तख्तियां लटकी रहा करती थीं-'कुत्तों से सावधान', 'कुत्ता काटता है' या 'घर में कुत्ता है।' इस तथ्य को चोरों ने अच्छी तरह समझ लिया है और वे सूने लावारिस घरों में ही चोरी करते हैं। लोग कुत्तों के डर से बस्ती की अपनी रौ में भी संभल-संभल कर आते हैं और चोर बेखटके चले आते हैं।

सावधान आप भी कुत्तों की हिटलिस्ट में हैं और वे कभी भी आपको काट सकते हैं। काटना कुत्तों के संस्कार में हैं। कुत्ते जन्मजात रोगी हैं और आदमी को रोगी बनाकर अपनी शक्ल में ढालना चाहते हैं। यों भी आदमी हालात से अर्द्धविक्षिप्त है और कुत्तों ने काट लिया तो पागल होने के भी चांस हैं।

-डॉ. तारादत्त निर्विरोध

स्वास्थ्य

स्वाइन फ्लू की चुनौती
कारण व निवारण

स्वाइन फ्लू आज न केवल भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है बल्कि कई देशों में वह अपने पांव पसार चुका है। कुछ ही दिन पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित किया। कुछ ही समय बाद भारत में स्वाइन फ्लू का कहर देखने को मिला। अब तक स्वाइन फ्लू ने भारत में भी कई जानें ले ली हैं। अगर इसे जल्द रोकने के उपाय नहीं खोजे गये तो मरने वालों की संख्या और ज्यादा हो सकती है।

स्वाइन फ्लू की शुरूआत मैक्सिको से हुई और अब यह पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। अब स्वाइन फ्लू कनाडा, मैक्सिको, हॉलैण्ड, जर्मनी, स्विटजरलैण्ड, ऑस्ट्रिया, स्पेन, इजराइल, भारत इत्यादि देशों में फैल चुका है।

स्वाइन फ्लू का असर उतना अधिक होगा जितनी कम रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी। जो मनुष्य कुपोषण से पीडित होंगे उनका इस महामारी के प्रभाव से बचना मुश्किल है। अगर अमेरिका एक विकसित अर्थव्यवस्था, स्वाइन फ्लू से बचने के लिए इतना संघर्षरत है तो विकासशील देशों को चिंता क्यों नहीं होगी। अमेरिका में सेंटर फॉर डिजीज सेंट्रल एण्ड प्रीवेंशन (सीडीडी) ने इस महामारी से लड़ने के लिए प्रयास किये और लोगों को इस समस्या के कारणों, लक्षणों और परिणामों से अवगत करवाया। दुनिया के 168 देश इस संक्रमण की गिरफ्त में आ चुके हैं और विषाणु की गिरफ्त जारी है।

भारत में भी इस महामारी की जड़ें फैलती जा रही हैं। सबसे पहले इस बीमारी का ग्रास हुई पूणे की 13 वर्षीय लड़की रिहा शेख। इसके उपरांत कई राज्य इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। भय के बादल हर दिशा में मंडरा रहे हैं। दिल्ली व पूना के स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। मुबई में बार और मल्टी प्लेक्स बंद कर दिये गये हैं। चण्डीगढ़ में 80 छात्रों में इस रोग के लक्षण मिले हैं। हैदराबाद में चल रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप पर भी स्वाइन फ्लू का साया पड़ा है। स्वाइन फ्लू की चपेट में आने से मलेशियाई टीम के कोच को आंध्र प्रदेश चेस्ट हास्पिटल में भर्ती करवाया गया है।

जिस प्रकार प्लेग चूहों से फैला था उसी प्रकार स्वाइन फ्लू सुअरों से होने वाला एक संक्रामक सांस सम्बन्धी रोग है। इसके वायरस को इंफ्लूएंजा (एच1एन1) के नाम से जाना जाता है। स्वाइन फ्लू मौसमी इंफ्लूएंजा से मिलता जुलता होता है। यह रोग निमोनिया जैसे घातक रोगों में बदल सकता है। बुखार, थकान, सिर दर्द, नाक बहना, गले में दर्द, खांसी, उल्टी होना आदि इसके मुख्य लक्षण हैं। इसके अतिरिक्त यह रोग फ्लू संक्रमित

● अजय शांडिल/प्रियंका वैद्य

व्यक्ति के सम्पर्क में आने से होता है क्योंकि स्वाइन फ्लू का वायरस मानव शरीर में श्वास के साथ प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार मनुष्य से मनुष्य संक्रमण होता है।

स्वाइन फ्लू निम्नलिखित कारणों से फैल सकता है-

-कम पके सूअर के मांस के भक्षण से।

-हवा में फैले वायरस से।

-मनुष्य से मनुष्य को।

-सुअर से मनुष्य को।

-कम रोग प्रतिरोधक क्षमता से अधिक संभावना।

-बुखार, खांसी और जुकाम से पीड़ित व्यक्ति के सम्पर्क से।

-कुपोषण से अधिक संभावना।

तथ्य यह है कि कोई भी महामारी हमारे राष्ट्र को तब तक क्षीण नहीं कर सकती जब तक हम तीन बातों का ध्यान रखेंगे। यह बातें हैं-जागरूकता, सावधानी और सहयोग।

कुछ उपायों द्वारा इस फ्लू से बचा जा सकता है।

-जिस व्यक्ति को बुखार और खंसी हो उसके सम्पर्क में न आयें।

-अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं और कई बार धोएं।

-इस रोग से प्रभावित व्यक्ति की देखरेख करते समय अपना मुंह व नाक ढक लें।

-भीड़ वाले स्थानों में कम से कम जायें।

-फ्लू से ग्रसित क्षेत्रों में जाने से बचें।

-अफवाहों पर ध्यान न दें तथा उचित स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें।

-अच्छी नींद लें, शारीरिक रूप से सक्रिय रहें तथा तनाव से बचें।

-स्वच्छ तथा अधिक मात्रा में पानी पीयें तथा पोषण युक्त भोजन का सेवन करें।

-विशेष तौर पर बच्चों, गर्भवती, महिलाओं, बुजुर्गों शूगर एवं दमें के मरीजों में यदि यह लक्षण हों तो तुरंत इलाज के लिए सम्पर्क करें।

-खुली हवा में सांस लें तथा योग क्रिया करें।

-डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा न लें।

इस प्रकार ऊपरलिखित बातों को ध्यान में रखें क्योंकि परहेज ही इलाज से बेहतर है।

स्वाइन फ्लू की रोकथाम हेतु केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार उचित कदम उठा रही हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्यूनिकेशन डिजीज ने पूरे देश में स्वाइन फ्लू की जांच हेतु प्रयोगशालाओं का विस्तार किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली में एक प्रयोगशाला स्थापित की है। इसके अतिरिक्त सरकार मीडिया के द्वारा स्वाइन फ्लू की जानकारी जनता तक पहुंचा रही है। सावधानी, सहयोग एवं साहस से ही स्वाइन फ्लू को मात दी जा सकती है। देश भर में स्वाइन फ्लू के आतंक को देखते हुए हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग भी हाई अलर्ट पर है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने जनसाधारण को स्वाइन फ्लू की सूचना देने के लिए टॉल फ्री नम्बर (1800-1808004) स्थापित किया है। प्रदेश के चिकित्सकों के एक दल को राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित किया गया है तथा अन्य चिकित्सकों तथा आम जनता को भी इस बारे जानकारी प्रदान करने के लिए राज्य तथा जिला स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से कारगरता से निपटने के लिए संचार, शिक्षा एवं संप्रेषण का कार्यक्रम भी बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। प्रदेश के दोनों मेडिकल कॉलेजों तथा जिला अस्पतालों में त्वरित कार्यवाही दल, आइसोलेशन बैड तथा सैम्पल एकत्र करने की सुविधा उपलब्ध करवायी गई है।

बाल कविता

पुस्तकें हैं महान

पुस्तकों में छिपा है
ज्ञान का भण्डार
इसलिए इनकी करना
सार-संभाल।
पुस्तकें सबकी मित्र हैं
यह हैं राह सुझाती
अंधकार से भटके मानव मन में
ज्ञान ज्योति जलाती।
पुस्तकें सबको
है अच्छा इंसान बनाती
कोई न छोटा
कोई न बड़ा
भाईचारा-मेलमिलाप का
सबको सबक सिखाती।
इसलिए बच्चों
पुस्तकों को रखना
हमेशा संभाल
इन्हें पढ़ना-पढ़ाना
अक्षरज्ञान का दीपक
घर-घर अवश्य जलाना।

▶▶ नरेश कुमार 'उदास'

पूर्वजों का स्मरण है श्राद्ध

शास्त्रों में आश्विन मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या तक की सब तिथियां श्राद्ध पक्ष में शुमार की गई हैं। कभी-कभी किसी एक तिथि का क्षय होने से दो श्राद्ध एक दिन भी आ जाते हैं। अनादिकाल से आश्विन मास के श्राद्ध पक्ष में भाद्रपद मास की पूर्णिमा का श्राद्ध शामिल नहीं था। ग्रंथों में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को ही श्राद्ध पक्ष माना गया है, जो विशेष रूप से पितरों का सम्मानित करने के लिए निर्धारित किया गया है। जहां तक आश्विन मास के शुक्ल पक्ष का सवाल है इसे देवपक्ष माना गया है। श्राद्ध पक्ष में भाद्रपद माह के एक पक्ष में अमावस्या व दूसरे पक्ष में पूर्णिमा आती है, इसलिए आश्विन मास कृष्ण पक्ष के पहले की भाद्रपद की पूर्णिमा को श्राद्ध से जोड़ा गया है। इसके पीछे यह तर्क दिया गया है कि जो पूर्वज पूर्णिमा को दिवंगत हुए हैं, उनकी तिथि की कृष्ण पक्ष वाले श्राद्ध पक्ष में कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे सर्वपितृ अमावस्या में सभी पितरों के श्राद्ध व्यवस्था है।

वाराहपुराण में पितरों की यशोगाथा का उल्लेख मिलता है, जिससे उनके स्मरण के महत्व और महात्मय को रेखांकित किया गया है। श्राद्ध में श्रद्धा का सम्पूर्ण अंश जुड़ा हुआ है। वस्तुत: श्राद्ध उस कर्मकांड को कहते हैं जो श्राद्ध से किया जाता है। पितरों तथा मृत व्यक्तियों के लिए किया गया सम्पूर्ण कार्य श्रद्धा की श्रेणी में आता है। श्राद्ध पितरों की तृप्ति के लिए शास्त्रीय विधि से किया गया धार्मिक कृत्य है। शास्त्रों में मनुष्यों के लिए तीन ऋण बताये गये हैं, जो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण कहलाते हैं। ऋषि ऋण ही गुरु ऋण का पर्याय है। परन्तु श्राद्ध का सम्बन्ध पितृ ऋण से है कर्मकांड मार्गप्रदीप में उल्लेखित है कि पितृ ऋण और पितृव्रत पूर्ण करने के लिए पूरे श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण और विशेष तिथि को श्राद्ध करने से पितृ ऋण शांत हो जाता है। पूरे पक्ष में ज्ञात- अज्ञात सभी पितरों का स्मरण किया जाता है। पूर्वजों की स्मृति को अक्षुण्ण रखने का यह एक धार्मिक साधन है।

पूर्वजों का स्मरण और उनकी पूजा जिसे श्राद्ध कहते हैं, वैदिक युग से ही प्रचलन में है। वेद की अनेक ऋचाओं में देवी-देवताओं को आहवान के साथ पितरों की भी प्रशस्ति की गई है। निमि ऋषि अत्रिकुल में उत्पन्न एक ऋषि थे। वे दत्तात्रेय के पुत्र थे और उन्होंने पितरों का श्राद्ध करने के पक्ष में अनेक कारणों पर प्रकाश डाला था। निमि के अनुसार श्राद्ध पक्ष में पितरों से प्रार्थना की जानी चाहिए कि वे अपने वंशजों के करीब आएं, अदृश्य आत्मिक स्वरूप होते हुए भी पितर आसन ग्रहण करें, हमारी पूजा स्वीकार करें और हमारे अपराधों को क्षमा करें। पके हुए चावलों का या तो आटे का गोला श्राद्ध में पितरों को अर्पित किया जाता है। इसमें तीन पीढ़ियों को पिंडदान किया जाता है-पितृ, पितामह और प्रपितामाह। ऐसी मान्यता है कि मंत्र शक्ति से पितरों तक वंशजों की यह

● अंकुश जैन

प्रार्थना पहुंच जाती है। मंत्रों का उच्चारण गोत्र उच्चारण के साथ करने से पितृ प्रार्थना स्वीकार करते हैं। श्रवण नक्षत्र में पितरों का श्राद्ध करने वाले मनुष्य का गृह कलह तुरंत नष्ट हो जाता है। आश्विन मास कृष्ण पक्ष के श्राद्ध पक्ष के अतिरिक्त चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के सात दिनों तक सात पितरों की पूजा करनी चाहिए, जिससे घर में व हर मंगल कार्य में किसी तरह का व्यवधान नहीं आता।

भविष्यपुराण में मुनि विश्वामृत का हवाला देकर बाहर प्रकार के श्राद्धों का वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण में भी श्राद्ध सम्बन्धी संदर्भ है। पहला, नित्य श्राद्ध है, जो प्रतिदिन किया जाता है। प्रतिदिन की क्रिया को 'नित्य' कहते हैं। दूसरा नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। तीसरा काम्य श्राद्ध है जो किसी कामना या सिद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। चौथा पार्वण श्राद्ध है, जो अमावस्या के विधान के अनुरूप किया जाता है। इसमें वृद्धि की कामना रहती है जैसे संतान प्राप्ति या परिवार के विवाह आदि। छठा श्राद्ध सपिंडन कहलाता है। इसमें प्रेत व पितरों के मिलन की इच्छा रहती है। ऐसी भी भावना रहती है कि प्रेत, पितरों की आत्माओं के साथ सहयोग का रुख रखें। सात से बारहवें प्रकार के श्राद्ध, कर्मांग, दैविक, यात्रार्थ और पुष्टवर्थ किया गया है। ऐसी भी मान्यता है कि पित्तरों के निमित्त दो यज्ञ किए जाते हैं, जो पिंडपितृयज्ञ तथा श्राद्ध कहते हैं। इसी संदर्भ में पितृव्रत भी किया जाता है, जिसमें एक वर्ष तक प्रति अमावस्या को इस व्रत का अनुष्ठान होता है। वर्ष के पूर्ण होने पर श्राद्ध कर वस्त्र, जलपूर्ण कलश और श्रद्धा हो तो गौ दान किया जाता है। इस प्रक्रिया से अनेक पीढ़ियां क्लेश मुक्त होकर तर जाती हैं। फिर पितृ तृप्त होने के बाद कामना करते हैं कि उनके कुल में ऐसे पुरुष की उत्पत्ति हो, जो सदाचारी, दयावान, धर्म में आस्था रखने वाला और लोकोपकारी हो। शास्त्रों के नियमों के अनुसार श्राद्ध का अधिकार केवल पुत्र को है। हो सकता है कि पुत्र की कामना के पीछे यह परम्परा भी एक वजह रही हो। पुत्र के अभाव में विधवा स्त्री को अपने पति का श्राद्ध करने का अधिकार दिया गया है। पुत्री के लिए पुत्र यानी नाती को भी श्राद्ध करने के योग्य माना गया है। व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए गोत्र भाई या किसी भी सगोत्री को श्राद्ध का अधिकार दिया गया है। श्राद्ध की प्रथा पूर्वज पूजा का ही एक विशिष्ट रूप है और दिवंगत प्रियजनों की आत्मा की शांति हेतु एक तर्पण है।

लघुकथा

आक्रोश

'कुछ दे दो बाबू जी। भगवान तुम्हारा भला करेगा।'

एक भिखारी बाजार में घूम रहा था। भीख के कटोरे के पैसे को उछाल-उछाल कर कहता जा रहा था, 'जो दोगे उसका दस गुना तुझको भगवान देगा... लाचार, अपाहिज पर दया करो।'

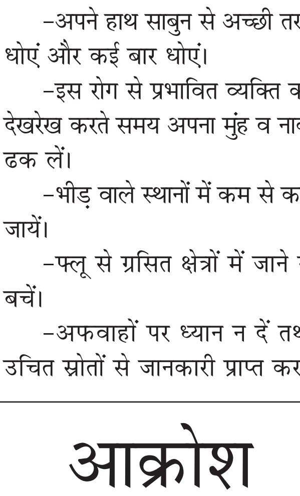

वह भीख मांगता उस बाजार के धनी दुकानदार की दुकान के समक्ष पहुंचा। वहां भी उसने अपनी फरियाद रखी।

सेठ जी ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, 'जा आगे बढ़।'

भिखारी जिद्द करने लगा, 'कुछ दे दो बाबू।...कल से भूखा हूं।'

'हूं...ह! चल हट! लगता है कमाकर रख दिया है यहां?'

'कुछ दे दो बाबू...।'

'मगज मत चाट।...ग्राहक का समय है।'

फिर भी भिखारी वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा था। सेठ ने ऊबकर कहा, 'अरे सोमट। ....भगाओ इसे यहां से नहीं तो मैं...।'

भिखारी का चेहरा तमतमा आया। आंखें लाल हो आई। वह वहां से तेजी से हट गया। सेठ की दुकान से दो कदम आगे बढ़कर बड़बड़ाया, 'जो बेचारा नहीं देता था, उसने तो नहीं दिया, पर जो साला रोड़ा देता था वह भी आज नहीं दिया।

...हे राम! और थूकते हुए वह आगे बढ़ गया।

-मुकुन्द लाल

पहाड़ी भाषा कनै साहित्य लोक मंच

fxfjjkt lkIrkfgd f'keyk] 2&8 flrEcj] 2009

लेख

इमाचल दी पच्छाण

● वंदना राणा

अपणे इमाचल जो वीरभूमि कणे कणे देवभूमि वी वोलदे, इत्थु दे लोक कुदरत विच प्रमात्मे जो दिक्खदे। इत्थु दे पहाड़ पत्थर, रस्ते- वांटां, खू-वांई, रुख-बूटे सब कैसी जो पूजदे। नौंईया फसला दा रोट बाबे जो चढ़ांदे, मुंडुया दे जमालू जालू करदे तां अपणिया कुलजा जो या फिरी अपणे-अपणे मणयो देवी-देवतेयां जो चढ़ांदे। इत्थु दे लोकगीतां विच रीति रिवाजां दी झलक मिलदी...। इत्थु इमाचले दा देया कोई वी संस्कार नी ऐ जेड़ा लोकगीतां दे वगैर होया... मतबल कि हर रीति-रिवाज कणे कोई न कोई लोकगीत गाया जांदा। कणे हर लोकगीत कणे कोई न कोई गाथा जुड़ियो ऐ। असां चाए कितनी वी तरक्की करी लैण पर असां उसी सादगिया कणे अपणे देवी देवतेयां जो मनांदे। कुत्थु वी चली जाण अपनी बोली-वोलना कदी नी पुलदे...।

अपना इमाचल मन्नया जाए तां इक तीर्थ नगरी ऐ; किंजा जित्थु हमीरपुरे च बावा बालक नाथ जी दा बड्डा मंदिर ऐ, उत्थु ऊने विच माता चिंतपुर्णी ऐ, मण्डिया च शिकारी देवी दा मंदिर ऐ। बोलदे, इस मंदिरे ऊपर छत नी ऐ, सैई इसदी पच्छाण ऐ। चम्बा बिच कैलाश पति शिव भोले बाबा जी दा डेरा ऐ, शिमले च कालीवाड़ी, संकट मोचन हनुमान जी दा मंदिर ऐ तां रामपुरे च भीमाकाली जी दा मंदिर ऐ, कांगड़े च मां ज्वाला जी दा कणे वज्रेश्वरी माता दा मंदिर ऐ। हरेक मंदिरे दा अपणा इक इतिहास ऐ। अज वी लोकां दी आस्था, विश्वास उंजा ई अपणे देवी-देवतयां ने जुड़या ऐ जिआं सूरजे कणे उसदी किरण जुड़ियो रैंदी।

अज असां जो दु:ख इसा गल्ला दा ऐ कि अपणी देवभूमि कुछ लोकां दे गल्त कमां ने दु:खी हौई ऐ इत्थु वाहरले मुल्खां ते माणू औंदे। कई रोजी-रोटी कमाणे खातर तां कुछ घुमना-फिरणा। कई माणु घुम्मी-फिरी ने अपणे-अपणे घरां जो चली जांदे कणे कुछ लोक इत्थु घर बनाई ने रैणा लगी पौंदे। जिसदिया वजह ने इक तां इमाचल प्रदेश दी अवादी बदादी, दूजे इत्थु आतंक, नशााखोरी कणे रोज-रोज देइयां घटणां घटा दियां, जिसदिया वजहा ने ऐ देवभूमि शर्मसार होया दि। अगली गल्ल कि पर्यावरण भी गंदा होया दा ऐ। अजकल मुंडू- कुडिया नशेयां करी ने देवभूमि इमाचले दा नां तां डुवोदेया हन्, इसदे कणे देश दी तरक्की विच वी रोड़ा बना दे, प्रदेश दी युवा-पीढ़ी जो इस बेले जागरूक होने दी कणे खरे मार्गदर्शन दी बथेरी लौड़ ऐ।

असां चाए कितणी वी तरक्की करी लैण, अपणी संस्कृति, अपणी वोली, अपणे संस्कार, रीतिरिवाज, लाण-खाण-पाण कणे अपणे पर्यावरण जो बचाई के रखणा उंगा-जेड़ी की इमाचले दी सच्ची-असल पच्छाण ऐ। इत्थु मिट्टिया दे कण-कण विच परमात्मा वसदे; ताईं तां इसजो देवभूमि बोलदे कणे हर वेले इसदा सजदा करदे।

मेरे इमाचले च आई के दिक्खा
इत्थु पहाड़ वी वोलदे,
नचदे-गांदे नदी-नालू,
कलौलां करदे पंख पखेरू...;

भ्यागा उठी करी
वांई पर जांई करी ख्वाजे मनां दे।
लोक गीत गांदे
खेतरां च कम कमांदे...!

लोकगीत
इत्थु दे रिवाजां दा शीशा
कण-कण मिट्टिया दा
जित्थु पजौंदा...,
उत्थु मेरा इमाचल बसदा...।

कबता

नशे रा कीड़

● हेमराज चौहान 'हेम'

बक्त बड़ा खराब आया लोको
समाजा खे लगा नशे रा कीड़
घड़ी-घड़ी दिन-दिन मरदे-ज्यूंदे
समझा ना आओ इना माणुआ री पीड़॥

दो पैसे री कमाई नी चार पैसे खर्च
ठेके खे बोलो गुरुद्वारा र चर्च
घरे बेशक भूखे मरो ए नी फिक्र
हर दूजे घरा दे लगा ए नशे रा मर्ज़।
आपी बिच्चे रिश्ते दे पड़ी गोई खीड़
समझ ना आओ इना माणुआ री पीड़।

नशे रे चक्करा दे भुले सब धर्म-कर्म
आमा-बापु सामणे बी नईं पीणे री शर्म
माया-धीया सड़का दे नईं चली सकदी
ठेके पांदे करनी आपणी जेबा नरम॥
लोक-लाज र धर्मा री चुटी गोई रीड़
समझ ना आओ इना माणुआ री पीड़

नशे री बमारी सब मिली जुली भगाओ
हाथ नी लाणा इदे कशम ए खाओ
बांका, सुंदर, तंदरुस्त अर् हरा-भरा
सब मेरे देशा अर् प्रदेशा खे बणाओ॥
फुला रे बाग 'हेमु' सरग छुंदे चीड़
समझ ऐबे आओ इना माणुआ री पीड़॥

सोच

सभवीं तैं छोट्टा कु:ण

● डॉ. पीयूष गुलेरी

सनसारे-च बड्डे-छोट्टे दी लड़ाई म्हेसां-ई रेह्ई। जुगां-जुगां तैं अपणाप्पे-की बड्डा सिद्ध करने दी होड़ा बिच मांहणू अणमिथियां गल्लां- बि करी गुजरदा। अपणे स्वार्थे जो साधणे-ताईं, बड्डा बणने ताईं, खरा सुणने दिया तांह्गा-च सैह दोस्तिया, रिश्तेदारिया, नातेदारिया कनैं उसूलां- जो-बि तिलांजली देई दिंदा। बड्डा बणी नैं दसणे दिया तांह्गा पचांह, बड्डा-क्हाणे दी छुटियाई किंह्यां कनैं कुसा बरीकिया-नैं जाले़ बुणदी रैंह्दी एह् बड्डे-बड्डे गयानियां-जो-बि सेह्ई नीं हुंदा। बस, पता तां ताह्लू चलदा जाह्लू 'डफ़-चारैं' हुंकारे दे गर्ते-च जाई पौंदा। फ्हिरी निक्कल़ना कोई असान-तां है नीं।

बड्डे कनैं छोटपणे-चकोई उमर खास मै:नै नीं रखदी। केई छोटिया उमरा दे बंदे ई इतणे बड्डे कनैं महान होई-चंदे भई दिखणे सुणने व्हाले़यां-जो नोख बझोंदा। कनैं केई बुढीखर होई-के-बि छोट्टेयां जो मात देई-यंदे कनैं अदेह्इयां हरकतां करदे भई बालक-याणेयां दिया हसोआणियां दे पात्तर बणी-यंदे-तांह्इयों गलांदे भई ग्याने दिया बड़ियाहया कनैं अक्कड़-हंकारे दिया छुटियाइया दा म्हेसा-तैं- ई इट्ट-बट्टे दा बैर-ई। जित्थू सद्बुद्धि, खरियाई, सीरत, सील सुभाअ, नरमयाई, लौह्कपणा कनैं नम्रता दा बास हुन्दा तित्थू अज-बि भला कनैं कल-बि भला। आपर जित्थू आक्कड़, हंकार, घमंड, बड़ियाइया दा गुरूर कम करदा तित्थू अजबि खैर नीं कनैं कल-बि खैर नीं। संत तुलसीदास उखां इसा गल्ला बखी किछ अपणे तौर-तीरके नैं समझांदेयां होयां गला:या ऐ :-

जहां सुमति वहां सम्मति नाना।
जहां कुमति तहां विपति विधाना।

गलाणे-रा मतलब ई भई जित्थी सद्बुद्धि आई तित्थी खरियाइया दा समुंदर ठाठ्ठां मारदा कनैं जित्थी दुर्बुद्धि घर करीयाए तित्थी कड़थयाह होई जांदा। बोलदे भई पापिये जो मारने ताईं तिह्दे पाप-ई बलवान होंदे। गलाणे दा मतलब-ऐ भई बुरेयां कनैं पापियां दिया मौता दा कारण तिह्नां- दा अपणा सोच कनैं अपणी-ई करनी, होणी बणी-नैं आईयांदी ऐ। हस-कनुआं महाभारते दा इक प्रसंग म्हारियां हाक्खीं खो:ड़ने ताईं भथेरा ऐ।

गल्ला-गल्ला-च गल आई तां छोटपणे दी होर गल सुणां। इक बरिया दी गल-ऐ भई अवंतिका नगरि मंझ जाह्लू-जी इक जनसभा खत्म होई-गेई तां तित्थी मुठभर बौद्ध भिक्षु कनैं असलीता जो जाणने-दी इच्छेया रखणे-व्हाले़ किछ खरे होर ग्यानी- ध्यानी लोक बची-गे। एह् सब्बो-ई गंभीर विचारवान लोक थे जिह्नां-दे मने च किछ जाणने दी खलल्ल-थी पेहयो।

भगवान श्रीकृष्ण होरां-जो जाह्लू-जी भरिया सभा मंझ शिशुपाल गाल़ीं लग्गा कड्ढणा तां तिह्नां मुस्करयाई- नैं तिस-जो मना कित्ता : 'ओ भाऊ! खा होस कर!!! मत बकैं गाल़ीं। कोई फैदा नीं। किछ होरे-दा-होर नां होई- याए। तेक्की कुथी इसदा खमियाजा नां भुगतणा पेईयाए।' अपर कुथू? शिशु पाले रे सिरे पर तां बड़ियाइया कनैं हंकारे दा भूत सवार था जहड़ा होणी बणी-नैं था घुम्मा क:रदा। साच्छाते विष्णु रा अवतार भगवान कृष्ण जितणा-तितणा तिसजो समझाणे दी कोस्त क:रन सैह् तितणा-तिणा ई गन्द बकणे दी जैस्ती करै। सगों बरसाते दे गन्दे सांह्ईं बिखरी-बिखरी जाए। खीर, जाह्लू-जी पाणी सिरैं-पराह्ल्लैं गुजरी गेया, तां भगवान श्रीकृष्ण होरां अपणा सुदर्शन चक्कर चलाया कनैं तिह्दे हंकारे दा मुंड ब:ढी दित्ता।

असल गल तां एह्-रे भई बन्दा अप्पूं-ई अपणिया करनियां दा फल़ भुगतदा। एह् खरयाई-बुरयाई तिह्दे अपणे-ई-ऐ इस-करी खरियाइया जो हौलै़-हौलै़ गलैं़ लांदे जाइये कनैं लगातार कोस्त करदे रेह्हये भई औगुणां तैं छुटकारा होंदा रैह। असां ग्लाअ क:रदे थे भई बड्डे कनैं छोटपये-च बरिहयां व्हालिया उमरा गिणतरिया दा कोई लेक्खा-जोक्खा कम नीं करदा सगों अपणापेप जो सुधारने ताईं खरियाइयां त्दी तांह्ग, उमरा-च छोट्टे मांह्णुआं जो-बि समें तैं पैह्ल्लैं बड्डा बणाई दिंदी। खरियाइया दे गुणां दी बूंद-बूंद कठरोई-नैं गंगासागर बणीयाए तां कोई चर्ज नीं।

गल्ला-गल्ला-च गल आई तां छोटपणे दी होर गल सुणां। इक बरिया दी गल-ऐ भई अवंतिका नगरि मंझ जाह्लू-जी इक जनसभा खत्म होई-गेई तां तित्थी मुठभर बौद्ध भिक्षु कनैं असलीता जो जाणने-दी इच्छेया रखणे-व्हाले़ किछ खरे होर ग्यानी- ध्यानी लोक बची-गे। एह् सब्बो-ई गंभीर विचारवान लोक थे जिह्नां-दे मने च किछ जाणने दी खलल्ल-थी पेहयो। सैह् बारी-बारी भगवान तथागत होरां-तैं अपणियां-अपणियां समस्यां कनैं गुल़ंणं दा समाधान-थे करोआअ क:रदे।

तेत्थी-ई इक लौह्किया बरेसा दा बालक-बि खडोत्तेया-था जिस री जिज्ञासा तिह्दे मूंहे पर साफ-थी झलका क:रदी। मौका थिहयोंदे यां-ई सैह् भगवान बुद्ध-व्हला पेश होया कनैं अपणे मनें अंदर पे:इया खौह्दल़ बारे-च पुच्छदा ऐ :- ''ठौकरा् मेरे साच्छात परमेसरा!! तू मिंजो एह् दस भई इस सनसारे मंझा सभनीं तैं छोट्टा कु:ण-ऐ?'' जागते ही उत्सुकता कनैं बुद्धिमता होर प्रतिभा जो भासदेयां भगवान बुद्ध किछ गंभीर- होई के बोल्ले:- जेह्ड़ा प्राणी सिर्फ कनैं सिर्फ अपणी-ई गल सोचदा-ऐ कनैं अपणे-ई स्वार्थे जो सभनीं-तैं उप्पर मनदा-ऐ, सैहयो जणां सभनी तैं छोट्टा-ऐ।''

अपणे इह्नां बोल्लां राहीं बड़े सरल तरीके नैं भिक्षुराज महाराजां जीवन-व्योहारे दे उच्चे अध्यात्मिक हारने री महान गल समझाई दित्ती-थी।

कांगड़ा ज़िला में स्थापित होंगे पर्यावरण मित्र उद्योग –किशन कपूर

उद्योग एवं श्रम रोज़गार मंत्री श्री किशन कपूर ने गत दिनों धर्मशाला में जानकारी देते हुए कहा कि कांगड़ा जिला में औद्योगिकरण की अपार संभावनाएं हैं तथा जिला में पर्यावरण मित्र एवं स्थानीय कच्चे माल पर आधारित उद्योग स्थापित करने पर बल दिया जाएगा ताकि जिला में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध हो सकें।

श्री किशन कपूर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जनवरी, 2003 में प्रदेश के लिये विशेष औद्योगिक पैकेज प्रदान किया गया था, परन्तु इस पैकेज़ के अन्तर्गत वर्ष 2007 तक पूर्व सरकार के कार्यकाल में कांगड़ा जिला में औद्योगिकरण के क्षेत्र में विशेष प्रगति नहीं हो पाई है, जोकि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जिला में उद्योग स्थापित करने के लिये अनुकूल जलवायु, प्रदूषण-रहित वातावरण एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

उद्योग मंत्री ने कहा कि जिला के अन्दरूनी भागों में उद्योग स्थापित करने हेतू ऐसे स्थलों का चयन किया जाएगा, जहां सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि कन्दरोड़ी, हटली, नगरी, नगरोटा बगवां इत्यादि क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये भूमि उपलब्ध है तथा धर्मशाला के आसपास भी औद्योगिकरण हेतू संभावना का पता लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्योगों में तैयार सामान को पड़ोसी राज्य पंजाब, जम्मू-कश्मीर इत्यादि प्रांतों में निर्यात किया जा सकता है।

उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक पैकेज़ की अवधि को बढ़ाने हेतू मामला केन्द्र सरकार के साथ प्रभावी ढंग से उठाया गया है तथा इस पैकेज़ की अवधि बढ़ने की संभावनाएं आपेक्षित हैं। उन्होंने कहा कि उद्योग स्थापित करने हेतू अबाधित विद्युत आपूर्ति होना अनिवार्य है जिसके लिये जिला के साथ लगते चम्बा जिला में विद्युत परियोजना चमेरा-1, चमेरा-2 कार्यरत हैं तथा चमेरा-3 का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा उद्योगपतियों को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति हेतू कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री किशन कपूर ने लोगों की समस्याओं को भी सुना तथा अधिकांश समस्याओं का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया।

दिल्ली में कार्यरत हिमाचल के कर्मचारियों को 24 नवम्बर का स्थानीय अवकाश

प्रदेश सरकार ने गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के अवसर पर दिल्ली स्थित हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत प्रदेश के कर्मचारियों के लिए आगामी 24 नवम्बर, 2009 को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश दैनिकभोगी कर्मियों को देय नहीं होगा तथा इसे नेगोशियेबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 की परिधि से बाहर रखा गया है।

जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए प्रवेश परीक्षा 10 अप्रैल 2010 को

जवाहर नवोदय विद्यालय चंबा के प्रधानाचार्य श्री डी.के. जैन ने गत दिनों जारी एक प्रेस वक्तव्य में बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय चंबा में 10 अप्रैल, 2010 को आयोजित की जाएगी, जिसके लिए, प्रास्पैक्ट्स, उपनिदेशक, ऐलीमेंट्री एजुकेशन चंबा के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं।

वन संशोधन विधेयक पारित

प्रदेश विधानसभा में भारतीय वन संशोधन विधेयक 2009 पारित कर दिया।

इस संशोधन विधेयक में भारतीय वन विधेयक के अधिकार क्षेत्र से उस वन भूमि को बाहर कर दिया है जिस पर कोई पौधे या जंगल नहीं है और जो पहले वेस्ट लैंड यानी बंजर भूमि के नाम से जानी जाती थी।

वन मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा विधेयक पर हुई चर्चा पर कहा कि वर्ष 1952 में जारी एक विज्ञप्ति के अंतर्गत बंजर भूमि को आरक्षित वन भूमि में लाकर इसे 1927 में बने भारतीय वन कानून के अधिकार क्षेत्र में ला दिया था। जिसे अब संशोधन द्वारा अब दोबारा इस विधेयक के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि 1980 का फोरेस्ट वन संरक्षण अधिनियम केवल उस भूमि पर लागू होता है जो वन भूमि की व्याख्या में आता है।

उन्होंने बताया कि क्योंकि अब वेस्ट लैंड को यानी बंजर भूमि को भारतीय वन अधिनियम अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया है इसलिए अब बंजर भूमि जिसकी मालिक सरकार है पर विकास कार्य किए जा सकेंगे जबकि इससे पहले इस भूमि के वनों के अलावा अन्य किसी भी उपयोग पर पाबंदी थी। चर्चा के दौरान इस संशोधन विधेयक को बनाए जाने का कांग्रेस के श्री कुलदीप सिंह पठानिया और हर्षवर्धन चौहान ने स्वागत किया था।

हमीरपुर में न्यायिक परिसर का लोकार्पण

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश श्री आर.बी. मिश्रा ने गत दिनों हमीरपुर में गत दिनों 3.71 करोड़ की लागत से निर्मित न्यायिक परिसर का उद्घाटन किया।

उन्होंने कहा कि न्याय प्रदान करने में विलम्ब न्याय न प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इस परिसर के बन जाने से न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आर. एल. रघु तथा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रतन सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

विधायकों के संशोधित वेतनमान विधेयक पारित

(पृष्ठ एक का शेष)

कहा कि यह खेद की बात है कि विधायकों व सांसदों को अपने वेतन व भत्ते बढ़ाने के लिए स्वयं पहल करनी पड़ती है। यदि केंद्र सरकार इस तरफ ध्यान दे, तो सभी के लिए एक जैसे मानदंड वेतन आयोग के माध्यम से संभव हो सकते हैं।

विधान सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

हिमाचल प्रदेश विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। गत तीन अगस्त से शुरू हुए विधान सभा मानसून सत्र के दौरान कुल 17 बैठकें हुईं। विधान सभा अध्यक्ष पंडित तुलसी राम ने सत्र के अंतिम दिन 27 अगस्त को बताया कि सत्र के दौरान कुल 626 प्रश्न आए जिनमें 452 तारांकित व 174 अतारांकित थे। इसके अलावा कुल सोलह विधेयक पारित हुए। अध्यक्ष ने कार्यवाही के दौरान सहयोग देने के लिए सत्ता पक्ष व विपक्ष के सभी सदस्यों का आभार जताया।

समापन के दौरान सत्ता पक्ष के नेता मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि यह मानूस सत्र अब तक का सबसे लंबा सत्र रहा, जिसकी वजह बजट सत्र के दौरान कम बैठकें होना है। मुख्य मंत्री ने सदन के सभी सदस्यों खासकर विपक्ष का धन्यवाद जताया। उन्होंने सदन की ओर से प्रदेश की जनता को आने वाले पर्वों दिवाली, दशहरा की भी शुभकामनाएं दीं।

स्कूल प्रमुखों के लिए ओरिएन्टेशन कार्यक्रम

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी स्कूलों के मुख्याध्यापकों एवं प्राचार्यों को सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान संबंधी मुद्दों पर जानकारी देने के उद्देश्य से राज्य परियोजना कार्यालय में तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किय गया है। इस कार्यशाला में प्रथम चरण में बिलासपुर जिला के लगभग 40 स्कूल प्रमुखों ने हिस्सा लिया।

कार्यशाला की अध्यक्षता सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने दी।

कार्यशाला में स्रोत व्यक्तियों द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों में मुख्याध्यापकों/प्राचार्यों की भूमिका एवं जिम्मेवारियों, अध्यापक सहयोग द्वारा शैक्षिक कार्य निष्पादन में प्रगति लाना, स्कूल प्रमुखों की प्रबन्धन एवं नेतृत्व क्षमता, स्कूली गतिविधियों, स्कूल विकास योजना, विशेष समूह/वर्गों की शिक्षा, कक्षा कक्ष शिक्षण में स्कूल प्रमुखों की भूमिका, कार्यालय प्रबंधन एवं वित्तीय प्रशासन संबंधी प्रशासनिक मुद्दों तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों संबंधी विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। स्कूल प्रमुखों द्वारा उठाए गए मुद्दों एवं सुझावों पर भी विचार विमर्श किया गया। शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के प्रयासों को अमलीजामा पहनाने में स्कूल प्रमुखों की भूमिका की महत्ता के दृष्टिगत इस प्रकार की राज्य स्तरीय कार्यशाला/कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अन्य जिलों के सभी स्कूली मुख्याध्यापकों एवं प्राचार्यों के लिए भी चरणबद्ध ढंग से आगामी दिनों में कार्यशालाओं का नियमित आयोजन किया जाएगा।

पौधरोपण में एक हजार करोड़ निवेश करेगी सिंगापुर की कम्पनी

(पृष्ठ एक का शेष)

मुख्य मंत्री ने कंपनी के निवेश प्रस्तावों का स्वागत करते हुए राज्य के उद्योगमित्र वातावरण में उद्यमियों को उपलब्ध करवायी जा रही सुविधाओं का विस्तृत ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित निवेश के लिए बेहतर कानून व्यवस्था उपलब्ध है तथा औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए अन्य आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग है तथा प्रदेश सरकार पौधरोपण की दिशा में सहयोग के लिए किसी भी परियोजना का स्वागत करेगी। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से न केवल प्रदेश के हरित आवरण में वृद्धि होगी बल्कि रोजगार एवं स्वरोजगार के माध्यम से स्थानीय लोगों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उनके इस प्रस्ताव को व्यवहारिक रूप देने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी।

प्रो. धूमल ने प्रतिनिधिमंडल को राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को हरा-भरा एवं औषधीय राज्य बनाने में जन सहयोग से आरंभ किए गए पौधरोपण अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में पेड़ों के कटान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है तथा राज्य के पारिस्थितिकीय संरक्षण के लिए ऐहतियाती उपायों के तौर पर पुनर्चक्रित पॉलीथीन बैग के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना को अंतिम रुप देने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करें।

वन मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने इस अवसर पर मुख्य मंत्री को परियोजना के विभिन्न घटकों के बारे तथा चरणबद्ध

शिक्षा मंत्री श्री ईश्वर दास धीमान तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्य मंत्री द्वारा वृक्षारोपण को जनअभियान बनाने का आह्वान

(पृष्ठ एक का शेष)

सके। उन्होंने प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे प्रदेश की वन संपदा तथा हरित आवरण को बढ़ाने में अपना पूर्ण सहयोग दें। उन्होंने कहा कि वन संपदा के संरक्षण की महत्ता तथा वैश्विक उष्मीकरण पर इसके प्रभावों के बारे में लोगों को जागरुक बनाने की आवश्यकता है।

मुख्य मंत्री ने क्षेत्र के लोगों को नव निर्मित पंचायत भवन का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक महिला मण्डल में महिला मण्डल भवन के निर्माण के प्रति प्रयासरत है।

मुख्य मंत्री ने शिक्षा विभाग के सर्वेक्षण के बाद स्थानीय उच्च पाठशाला को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का आश्वासन दिया। उन्होंने नेहरा में मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये स्वीकृत किए। घनाहट्टी-भूखड- थाच सड़क के सुधार एवं पक्का करने की घोषणा की। उन्होंने अन्य स्थानीय मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

प्रो. धूमल ने बर्ल्ड वाईल्ड लाईफ स्टेडियम फॉर नेचर हिमाचल प्रदेश की निदेशक श्रीमती वंदना थपलियाल को सम्मानित किया, जिन्होंने राज्य महिला मोर्चा द्वारा घरोग में रोपित पौधों के संरक्षण का उत्तरायित्व लिया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्रीमती सरवीण चौधरी ने प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान आरंभ करने के लिए राज्य भाजपा महिला मोर्चा के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण को राज्य सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से पहले ही पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर, विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित बनाई है।

सांसद श्री वीरेन्द्र कश्यप ने लोक सभा चुनावों में उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया तथा आश्वासन दिया कि वे क्षेत्र तथा प्रदेश की विकास मांगों को संसद में उठाते रहेंगे।

राज्य भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती रूपा शर्मा ने मुख्य मंत्री का स्वागत किया ।

ग्राम पंचायत नेहरा-घन्योग के प्रधान श्री चमन लाल ने भी अवसर पर अपने विचार व्यक्त किये।

राज्य भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव श्रीमती रितु सेठी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

पूर्व विधायक श्री भगत राम, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती अम्बिका सूद, भाजपा महिला मोर्चा महासचिव श्रीमती बीना ठाकुर, जिला शिमला भाजपा के अध्यक्ष श्री गणेश दत्त, राज्य भाजपा के सचिव श्री एच. एन. कश्यप, राष्ट्रीय भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष श्री तरसेम भारती, भाजपा मंडल के अध्यक्ष श्री देव राज, कुसुम्पटी भाजपा मंडल के अध्यक्ष श्री दिनेश्वर कश्यप, वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

जल संरक्षण उपाय अपनाने वालों को पुरस्कृत करेगी सरकार

(पृष्ठ एक का शेष)

योजनाओं के माध्यम से जल संवर्द्धन की उपलब्धता के लिए ज्यादातर सामान्य दृष्टिकोण अपनाया जाता है, क्योंकि इनकी तकनीकी एवं आर्थिक सीमा है।

प्रो. धूमल ने कहा कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को 'जल लेखा' करने की आवश्यकता है ताकि जल की उपलब्धता एवं उपयोग में लाए गए जल के बीच के अंतर का अनुमान लगाया जा सके, जिसके लिए, पानी की फिजूलखर्ची को रोकने के लिए प्रभावी प्रणाली विकसित की जा सके। उन्होंने इस वित्त वर्ष के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल प्रपात प्रबंधन उपायों में प्राथमिकता का विस्तार देने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

मुख्य मंत्री ने कहा कि 49.50 करोड़ रुपये के विश्व बैंक वित्तपोषित हाइड्रोलॉजी प्रोजैक्ट प्रदेश सरकार द्वारा जल प्रबंधन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में सहयोग प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण की दिशा में अनेक पग उठाए हैं, जिनमें 47 वर्षा जल संग्रहण ढांचे तथा 'एक्सेलरेटिड इरिगेशन प्रोग्राम एण्ड आर्टिफिशियल रिचार्ज प्रोजेक्ट 'भू-जल प्रबंधन एवं नियमीकरण' के अंतर्गत 42.27 करोड़ रुपये की लागत से जल इकाई योजनाएं आरंभ की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी विभागों को 'रूफ टॉप वॉटर स्ट्रक्चर' के निर्माण के लिए पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं तथा अभी तक इस तरह के 107 निर्माण किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मण्डल में पायलट योजना के तौर पर कम से कम एक वर्षा जल संग्रहण ढांचे के निर्माण के लिए प्रभावी प्रयास किये गये हैं।

जल प्रबन्धन के लिए आपसी सहयोग पर बल

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि प्रदेश में गठित जल प्रबन्धन बोर्ड सम्बद्ध विभागों तथा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एन.ए.पी.सी.सी) के तहत गठित राष्ट्रीय मिशनों से जुड़े केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ बेहतर तालमेल के साथ कार्य करेगा।

प्रो. धूमल ने कहा कि प्रदेश में इस बोर्ड के गठन का उद्देश्य जल संग्रहण एवं संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को सफल बनाने के लिए सभी सरकारी विभागों तथा केन्द्र सरकार के मंत्रालयों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। जल संग्रहण एवं संरक्षण गतिविधियों में तेजी लाने के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा तथा प्रारंभ में उन 15 खण्डों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा जहां जल की कमी है।

मुख्य मंत्री ने जल संरक्षण की वचनबद्धता को दोहराते हुए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग तथा केन्द्रीय जल आयोग एवं केन्द्रीय भू-जल बोर्ड जैसी केन्द्रीय एजेंसियों को इस सम्बन्ध में सार्थक प्रयास करने का परामर्श दिया।

मुख्य सचिव श्रीमती आशा स्वरूप ने वॉटरशैड विकास पर मास्टर प्लान तैयार करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इस संबंध में जल प्रबन्धन बोर्ड को कोई कारगर योजना तैयार करनी चाहिए, ताकि चिन्हित परियोजनाओं के तहत वर्षा जल संग्रहण उपायों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ भूमिगत जल स्रोतों को 'रिचार्ज' करने में भी सहायता मिल सके।

प्रधान सचिव सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य श्री नरेन्द्र चौहान ने जल प्रबंधन बोर्ड की प्रथम बैठक की कार्यवाही का संचालन किया तथा राज्य में इस बोर्ड के गठन के उद्देश्यों की जानकारी दी।

प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बनेंगी पन्द्रह सुरंगें

हिमाचल में अब दूरियों को सुरंगों के माध्यम से मिटाने के प्रयास हो रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पंद्रह सुरंगें प्रस्तावित हैं। आठ सुरंगों की प्री फीजिबिल्टी रिपोर्ट तैयार कर डीपीआर बनाई जा रही है। धनेटा-बंगाणा, जोगिन्द्रनगर-कुल्लू और हाली-उतराला सुरंगों को प्राथमिकता के आधार पर बनाया जा रहा है। तीनों सुरंगों के लिए सरकार ने 2.17 करोड़ दिये हैं। सुरंगें बीओटी आधार पर पब्लिक प्राइवेट भागीदारी से बनाई जायेंगी। विधानसभा में मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि सुरंगों से जहां दूरियां कम होंगी, वहीं पर्यावरण भी सुरक्षित होगा।

मुख्य मंत्री विधायक सुखविन्द्र सिंह सुक्खू द्वारा नियम 63 के तहत प्रदेश में सुरंगों के निर्माण के बारे में उठाई गई चर्चा का जवाब दे रहे थे। लोक निर्माण मंत्री श्री गुलाब सिंह ने कहा कि बंगाणा-धनेटा (35 करोड़), जोगिन्द्रनगर-कुल्लू (50 करोड़) और होली-उतराला (145 करोड़) सुरंगों को प्राथमिकता के आधार पर बनाया जा रहा है। ऊना-हमीरपुर, मण्डी-कुल्लू और चम्बा-कांगड़ा को जोड़ने वाली इन सुरंगों की डीपीआर तैयार की जा रही है। शिमला के हिमफैड पेट्रोल पम्प से आइजीएमसी, लिफ्ट से हिमफैड पेट्रोल पम्प, खड़ा पत्थर, स्वारघाट और रानीताल से भी सुरंगों के निर्माण पर निर्णय ले लिया गया है।

तीसा-किलाड़, जलोड़ी जोत, देवीगढ़, नौणी-जामुन, बिलासपुर-जोबल, लिफ्ट-लक्कड़ बाजार और संजौली-ढली के लिए भी सुरंगें बनाने के प्रस्ताव हैं। वित्त पोषण के लिए तेरहवें वित्त आयोग को प्रस्ताव भेजने के अलावा विश्व बैंक, एडीपी के माध्यम से भी धन जुटाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल शिमला जिला के नैहरा में पंचायत भवन का उद्घाटन करते हुए।

टांडा में बनेगा नर्सिंग सेंटर ऑफ एक्सीलैंस

कांगड़ा के टांडा में नर्सिंग का सेंटर ऑफ एक्सीलैंस बनेगा। इस पर बीस करोड़ खर्च होंगे। यहां नर्सिंग में सुपर स्पेशलाइजेशन होगी। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम के अलावा नर्सिंग के अपग्रेड कोर्स भी इस सेंटर में हो सकेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए प्रदेश सरकार ने मसौदा तैयार कर केन्द्र को भेज दिया है। विधानसभा में विधायक श्री राजेश धर्माणी के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव बिंदल ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि राज्य में 27 नर्सिंग स्कूल खुलना प्रस्तावित है, जिनमें इसी वर्ष जीएनएम के लिए 1140 लड़कियां प्रवेश ले सकेंगी। इसके अलावा प्रस्तावित चौदह बीएससी नर्सिंग कॉलेजों में 620 सीटें भरी जायेंगी। नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया ने ज्यादातर स्कूलों को मंजूरी दे दी है, जबकि कुछ की इंस्पेक्शन की जा रही है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग के कुछ सरकारी संस्थानों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इनमें से कइयों को काउंसिल ने स्वीकृति दे दी थी। डॉ. बिंदल ने कहा कि पिछले सात वर्षों के दौरान सरकारी नर्सिंग संस्थानों में कोई भी बैच नहीं बिठाया गया, जिससे सूबे में प्रशिक्षित नर्सों की भारी कमी हुई।

प्रदेश के प्रमुख शहरों में बनेंगी आधुनिक पार्किंग

परिवहन मंत्री महेन्द्र सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार हिमाचल के प्रमुख शहरों में आधुनिक पार्किंग बनाएगी। राजधानी शिमला में सात नये स्थल चिन्हित किये गये हैं। सुन्दरनगर, मण्डी समेत हर जिले के प्रमुख शहरों में प्राथमिकता से पार्किंग का निर्माण किया जायेगा। पालमपुर में प्रस्तावित पार्किंग को बीओटी के आधार पर बनाने के लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट तैयार होते ही पालमपुर में पार्किंग बना दी जायेगी। महेन्द्र सिंह ने यह जानकारी विधायक प्रवीण शर्मा के सवाल के जवाब में विधानसभा में दी। उन्होंने कहा कि तकनीकी मंजूरी न मिलने के कारण पालमपुर में पार्किंग प्रोजेक्ट का काम शुरू नहीं किया जा सका है। विधायक उर्मिल ठाकुर के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि हमीरपुर में बस अड्डा बनाने के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। बीओटी के आधार पर यहां बस अड्डा बनाया जायेगा।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने को सरकार वचनबद्ध-प्रो. धूमल

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि प्रदेश सरकार केन्द्रीय विश्वविद्यालय को खोलने के प्रति गंभीर है। उन्होंने कहा कि इसके लिए केन्द्र सरकार के समक्ष देहरा में छह सौ एकड़ भूमि उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। इसी तरह कुछ अन्य स्थानों पर भी भूमि उपलब्ध करवाने की बात कही गई थी।

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम एवं ऑस्कर फर्नाडीज ने प्रदेश को केन्द्रीय विश्वविद्यालय देने की घोषणा की थी। उन्होंने इसके लिए विपक्ष की तरफ से साझे प्रयास करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए केन्द्र से मिलने वाली योजनाओं में विलम्ब न हो इसके लिए मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है।

शिक्षा मंत्री श्री ईश्वर दास धीमान ने विधानसभा में इस मामले में विधायक जीएस बाली की तरफ से नियम-62 के तहत लाये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए कहा कि प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय समय पर आये, इसके लिए सरकार वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश सरकार केन्द्र की पूरी मदद कर रही है तथा जमीन हस्तांतरित करने सहित सभी औपचारिकताओं को पूरा किया गया है।

> जमीन हस्तांतरण सहित सभी औपचारिकताएं पूरी

उन्होंने केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना बारे मुख्य मंत्री के प्रयासों को सराहा। इससे पूर्व विधायक जीएस बाली ने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में केन्द्रीय विश्वविद्यालय के खुलने में हो रही देरी का मामला उठाया।

सड़क अधोसंरचना को सुदृढ़ करने बारे विचार विमर्श

मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री नागेन्द्र सिंह नागौड़ ने गत दिनों शिमला में मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल से भेंट की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी।

बाद में, श्री नागेन्द्र सिंह नागौड़ ने हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री गुलाब सिंह ठाकुर से भेंट कर उनसे दोनों राज्य सरकारों की नीतियों एवं विकास कार्यक्रमों, विशेषकर सड़क अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के बारे में विचार-विमर्श किया। श्री सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक सुन्दर राज्य है लेकिन इसका अधिकतर भौगोलिक क्षेत्र पहाड़ी एवं पर्वतीय होने के कारण यहां सड़क तथा अन्य निर्माण कार्यों को पूरा करने में मैदानी राज्यों की अपेक्षा अधिक धन एवं समय की आवश्यकता रहती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य उच्च मार्गों का रखरखाव मध्यप्रदेश राज्य विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है।

> मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री की मुख्य मंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री से भेंट

श्री गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है, जहां 11 राष्ट्रीय उच्च मार्गों की कुल लंबाई 14000 कि.मी. है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 10 राज्य उच्च मार्गों को विश्व बैंक वित्तपोषण से एक्सप्रेस हाईवे के रूप में विकसित करने के लिए सड़क अधोसंरचना विकास निगम (आर.आई.डी.सी) को सौंपी गई है। प्रदेश के अन्य राज्य उच्च मार्गों, प्रमुख जिला सड़क मार्गों तथा प्रधानमंत्री सड़क योजना सहित अन्य ग्रामीण सड़कों का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। मुख्य संसदीय सचिव श्री वीरेन्द्र कंवर, विधायकगण सर्वश्री सुरेश भारद्वाज, रणधीर शर्मा, राजीव सेजल, श्री गोबिन्द राम शर्मा एवं तेजवंत नेगी, लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर- इन-चीफ श्री अरूण महाजन तथा प्रदेश सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त गुणात्मक शिक्षा

भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए एक नयी योजना आरंभ की गई है, जिसमें अधिसूचित शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को दस जमा दो कक्षाओं के बाद शिक्षा ग्रहण करने के लिए मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एक प्रवक्ता ने गत दिनों शिमला में दी।

> केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना

उन्होंने कहा कि अधिसूचित संस्थानों की जानकारी विभाग की वैबसाइट www.socialjustice.nic.in पर भी उपलब्ध है। प्रवक्ता ने कहा कि इन अधिसूचित संस्थानों में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को शिक्षा जारी रखने हेतु उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु छात्रवृत्ति दी जाएगी। निजी क्षेत्र में स्थापित संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को अधिकतम 2 लाख रुपये वार्षिक प्रति विद्यार्थी तथा निजी क्षेत्र के 'लाईग क्लबों' में पायलट का प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को 3.72 लाख रुपये वार्षिक प्रति विद्यार्थी दी जाएगी। यह छात्रवृत्ति विद्यार्थियों की संतोषजनक अध्ययन रिपोर्ट की स्थिति में कोर्स के पूरा होने तक जारी रहेगी, जिसके लिए पात्र उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

राज्य स्तरीय कैंपा प्राधिकरण गठित

प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय कैंपा प्राधिकरण का गठन कर दिया है। इसके गठन से राज्य में वनीकरण, वन संसाधन प्रबन्धन, प्राकृतिक वनों के संरक्षण, वाइल्ड लाइफ का प्रबन्धन और अन्य वानिकी गतिविधियों को तेज किया जा सकेगा। यह जानकारी वन मंत्री जेपी नड्डा ने विधानसभा में दी। उन्होंने कहा कि कैंपा के तहत जमा धन का प्रबन्धन मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में बनी गवर्निंग बॉडी तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा होंगे।

श्री नड्डा ने कहा कि राज्य सरकार ने गत 21 अगस्त को भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय स्तर की कैंपा से 36.67 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। यह राशि कैंपा में कई राज्य के हिस्से की 10 फीसदी है। उन्होंने कहा कि कैंपा फण्ड की पहली किस्त का प्रयोग पौधरोपण, मृदा संरक्षण के कार्यों और सतलुज, रावी, व्यास नदियों के कैचमेंट एरिया में वन प्रबन्धन के कार्य पर खर्च होगा।

नड्डा ने बताया कि वन विभाग ने पीपल और बरगद का पौधरोपण अभियान चलाया है। पीपल और बरगद के पौधरोपण का नौ हजार गांवों में सर्वे किया गया था और इसमें से 3057 गांवों को चुना गया था। उन्होंने कहा कि अभी तक 8538 पौधों में से 5073 पौधे पीपल तथा 4436 बरगद के लगा दिये गये हैं और ये पौधे धार्मिक स्थलों, स्कूल, पंचायत घर और सरकारी कम्पनियों के परिसरों में लगाये गये हैं और इसके अलावा बावड़ियों, जल स्रोतों के आसपास भी इनका पौधरोपण किया गया है।

भेड़पालकों के दल का जम्मू-कश्मीर भ्रमण

21 सदस्यीय भेड़ पालकों के एक दल ने हिमाचल प्रदेश ऊन उत्पादक संघ के अध्यक्ष श्री त्रिलोक कपूर की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर के द्रास क्षेत्र का भ्रमण किया तथा कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शहीदों की स्मृति में द्रास में स्थित फोटो गैलरी का अवलोकन भी किया। प्रतिनिधिमंडल ने श्रीनगर में डॉ. आर.एस. खान प्रबंध निदेशक 'शीप ब्रीडिंग' विभाग, डॉ. यूसुफ हसन निदेशक ऊन बोर्ड तथा डॉ. जे.सी. शर्मा, निदेशक पशुपालन विभाग सहित वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिले। प्रतिनिधिमंडल इन दिनों जम्मू कश्मीर में हिमाचल प्रदेश राज्य ऊन उत्पादक संघ व द्रास कारगिल मध्य हिमालय जलागम परियोजना के संयुक्त तत्वावधान में अध्ययन भ्रमण पर है। इस प्रकार का यह पहला अध्ययन भ्रमण है जो जम्मू में भेड़पालन हेतु अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकों की जानकारी प्राप्त करने के लिए कश्मीर के ठण्डे क्षेत्रों में आयोजित किया जा रहा है।

iedk'kd ch-Mh- 'kekZ fun'kd lpuk ,o tu lEidZ foHkkx fg-i- f'keyk&171002] eædd jkthó dekj 'kdj fu;=d] eæ.k rFkk y[ku lkexh foHkkx f'keyk&171005] Qku 2830378] i/kku lEikndd ch-Mh- 'kekZ] ofj"B lEikndd vkj-,l- uxh] lEikndd ;knfoUnj flg pkgku] dk;ky;% fg-i- eæ.kky; ifjlj] f'keyk&171005] Qku o QDl% 2633145] b&ey% girirajhp@gmail.com., girirajhp@yahoo.co.in OR girirajweekly 1978 @yahoo.co. in ikfIr LFkku% fxfjjkt dk;ky;A ¼fxfjjkt lkIrkfgd esa idkf'kr y[kks esa 0;Dr fopkjks ls lEiknd;h; lgefr vfuok;Z ugh½